**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**SOUTHERN ZONE, CHENNAI**
**IN**
**ORIGINAL APPLICATION No. 72 of 2021**

**IN THE MATTER OF:-**

P.R. Sasi Kumar and Anr. ....Applicant (s)

VERSUS

Union of India & Ors. ....Respondent (s)

**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1, MINISTRY OF ENVIRONMETNAL, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -**

I, Dr. Murali Krishna working as Scientist-D in the Integrated Regional Office, Bangalore in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC), the deponent herein do hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1. That I am competent to swear the present counter affidavit on behalf of MoEF&CC.
2. That I have perused the contents of the above captioned application filed by the Applicant and I am duly authorized to depose by way of the present affidavit.

3. That the contents of the application, unless specifically admitted, are denied to the extent that they are inconsistent with submissions made hereinafter.

4. That the applicant has filed this application praying *inter-alia* for directing the Respondent No.3 (Kerala Rail Development Corporation Limited) not to carry out the construction activities of a project viz " Silverline Project" (Semi High Speed Rail from Thiruvananthapuram to Kasaragod a joint venture company of Ministry of Railways and Government of Kerala) without obtaining the prior EC.

5. That the answering respondent has issued an Environmental Impact Assessment (EIA) Notification Number S.O. 1533 E dated 14, September 2006 superseding the Environmental Impact Assessment Notification 1994. The EIA Notification, 2006 regulates developmental projects in different parts of the country. **A copy of EIA Notification, 2006 is annexed herewith as Annexure-1.**

6. That **EIA Notification, 2006 covers 39 project/activity** in its Schedule which *inter-alia,* includes different types of infrastructure projects viz. Airports, Ports, Highways, Building & Construction Projects etc. as specified and categorized in the said schedule.

7. That the **Railways or Railways Projects are not within the purview of EIA Notification, 2006**. Thereby, the project in question is not required to obtain prior Environment Clearance.

8. That the Application No 478 of 2015, as referred by the petitioner, had been filed by Vikrant Kumar Tongad in Hon'ble NGT regarding requirement of obtaining the Environmental Clearance for the Metro Construction from Noida to Greater Noida and the same was **disposed of on 31.05.2016** with the following direction:

> *"1. We hold and declare that the project in question, that is, the Metro Construction from Noida to Greater Noida is a project covered under Entry 8(b) of the Schedule to the Notification of 2006.*
>
> *2. We direct the respondent no.1, the project proponent to obtain Environmental Clearance for the project in question as expeditiously as possible and in any case not beyond three months from the date of pronouncement of this judgment. The application in Form 1A shall be submitted within one week from today to SEIAA, Uttar Pradesh. It shall dispose of the application as Category B-1 project as expeditiously as possible, and in any case, not later than the period aforestated.*
>
> *3. SEIAA shall impose conditions, both in regard to the remedial measures as well as for completion of the project in terms of the Notification of 2006 and protection of the environment and ecology in that area.*
>
> *4. We make it clear that if the work already executed by the project proponent has caused any irretrievable loss to environment, ecology and nature, the SEIAA would be well within its rights even to direct demolition of such constructed portion.*

*5. The order granting Environmental Clearance shall be specific in regard to the remedial as well as precautionary measures that are required to be taken by the project proponent.*

*6. In the event the project proponent does not comply with the directions issued under the Environmental Clearance, the project work shall be liable to be stopped forthwith."*

**A copy of the order dated 31.05.2016 is annexed as Annexure-2.**

9. That it is also submitted that order dated 31.05.2016 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Application No. 478 of 2015 titled as Vikrant Tongad Vs Noida Metro Rail Corporation & Ors. was challenged by way of **Civil Appeal No. 9070 of 2016 in Hon'ble Supreme Court of India** and the same has been **stayed vide order dated 16.09.2016.** The direction vide order dated 16.09.2016 are as follows:

*"Heard*

*Issue Notice*

*Pending further order from this court impugned orders passed by the National Green Tribunal, Principal Bench, shall remain stayed."*

**A Copy of order dated 16.09.2016 is annexed as Annexure-3.**

10. That the answering respondent has not received any application for grant of Environmental Clearance for the project in question

11. It is submitted that the present counter affidavit may kindly be taken on record and into consideration and the Hon'ble Tribunal may pass appropriate Order(s), direction(s) as deemed fit and proper under the facts and circumstances of the present case which the answering Respondent shall duly comply with.

12. That other/ancillary issues raised in the application under reply do not pertain to the answering respondent. The answering respondent seeks leave to make additional submissions, if required, during the course of the proceedings

**DEPONENT**

Dr. Murali Krishna Chimata
Scientist "D"
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office, (Southern Zone),
Kendriya Sadan, Koramangala
Bengaluru-560034

**VERIFICATION: -**

Verified at Bangalore on this the 1st day of September 2021 that the contents of the above reply are true and correct, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

**DEPONENT**

Dr. Murali Krishna Chimata
Scientist "D"
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office, (Southern Zone),
Kendriya Sadan, Koramangala
Bengaluru-560034

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
No. 1067] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

**का.आ. 1533(अ).**—केंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गठित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में[1], नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समाघातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का0आ0 सं0 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना सं0 का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस अधिसूचना मे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 के

---

[1] भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खंड और अनन्य आर्थिक जोन सम्मिलित है ।

अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा ।

**2. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षाएं (ई.सी.) :-**

निम्नलिखित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, कोई संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पूर्व उक्त अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से, जिसे अनुसूची में 'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहा गया है, और राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कहा गया है, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी जब परियोजना या क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है ।

(i) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाएं या क्रियाकलाप ;

(ii) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का, संबंधित क्षेत्र के लिए अर्थात् परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए जो विस्तार या आधुनिकीकरण के पश्चात् अनुसूची में दी गई अधिकतम सीमाओं को पार कर लेते हैं, क्षमता में परिवर्धन सहित विस्तार या आधुनिकीकरण ;

(iii) विनिर्दिष्ट रेंज से परे अनुसूची में सम्मिलित किसी विद्यमान विनिर्माणकर्ता यूनिट में उत्पाद मिश्रण में कोई परिवर्तन ।

**3. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण :-**(1) कोई राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिसे इसमे इसके पश्चात् एसईआईएए कहा गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित किया जाएगा जिसमें तीन सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव, राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(2) सदस्य-सचिव संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सेवारत अधिकारी होगा जो पर्यावरण विधियों से परिचित होगा ।

(3) अन्य दो सदस्य या तो वृत्तिक या विशेषज्ञ होंगे जो इस अधिसूचना के परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी को पूरा करते हों ।

(4) ऊपर उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य जो पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया में विशेषज्ञ हो, एसईआईएए का अध्यक्ष होगा ।

(5) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपपैरा (3) से उपपैरा (4) में निर्दिष्ट सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी और केन्द्रीय सरकार नामों के प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईएए को एक प्राधिकरण के रूप में गठित करेगी ।

(6) गैर पदधारी सदस्य और अध्यक्ष की (प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से) तीन वर्षों की नियत पदावधि होगी ।

(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय एकमत से होंगे और किसी बैठक में लिए जाएंगे ।

**4. परियोजना और क्रियाकलापों का प्रवर्गीकरण :–**

(i) सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप मुख्यतः दो प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत हैं- प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' सक्षम समाघात की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों पर आधारित हैं ।

(ii) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सम्मिलित है, के लिए, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी ;

(iii) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत पैरा 2 के उपपैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण या पैरा 2 के उपपैरा (iii) में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन भी हैं, किन्तु जिसमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो अनुसूची में निश्चित की गई साधारण शर्तों को पूरा करते हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी । एसईआईएए का अपना विनिश्चय, इस इस अधिसूचना में गठित की जाने वाली किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों पर आधारित होगा । एसईआईएए सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में, कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी ;

5. **स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन समिति :-** केंद्रीय सरकार के स्तर पर वही विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य या संघ राज्य स्तर पर राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईएसी और एसईएसी कहा गया है) क्रमशः प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों की स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन करेंगी । ईएसी और एसईएसी की प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(क) ईएसी की संरचना परिशिष्ट VI में दी जाएगी । राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एसईएसी का गठन संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से समान संरचना सहित गठन किया जाएगा ।

(ख) केंद्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की पूर्व सहमति से प्रशासनिक सुविधा और लागत के कारणों से एक या अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी का गठन कर सकेगी ।

(ग) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी ।

(घ) संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति के प्राधिकृत सदस्य उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगी गई है, को स्क्रीन करने या विस्तार करने या आंकलन के प्रयोजनों के लिए आवेदक को जो निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा, कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देंगे ।

(ङ) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेगी । अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति बनाने का प्रयास करेगा और सहमति नहीं बन पाती है तो बहुमत का विचार माना जाएगा ।

6. **पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन (ईसी) :-** सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए कोई आवेदन, परियोजना और/या क्रियाकलापों के लिए, जिससे आवेदन संबंधित है, आवेदक द्वारा स्थल पर किसी सन्निर्माण क्रियाकलाप या भूमि की तैयारी के प्रारंभ के पूर्व, पूर्वेक्षित स्थल (स्थलों) की पहचान के पश्चात् परिशिष्ट 2 दिया गया है, यदि लागू हों, इससे संलग्न प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क में किया जाएगा । आवेदक, उसके सिवाय, सन्निर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की मद 8) के मामले में प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क के अतिरिक्त पूर्व साध्यता परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति, पूर्व साध्यता रिपोर्ट के स्थान पर धारणा योजना की एक प्रति आवेदन के साथ पेश करेगा ।

7. (i) **नई परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) प्रक्रिया के प्रक्रम :-** नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया में अधिकतम चार प्रक्रम समाविष्ट होंगे, जिनमें से सभी इस अधिसूचना में नीचे यथाउपवर्णित विशिष्ट मामलों में लागू नहीं होंगे, ये चार प्रक्रम श्रृंखलाबद्ध क्रम में होंगे :--

- प्रक्रम (1) स्क्रीनिंग (केवल प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए)
- प्रक्रम (2) विस्तारण
- प्रक्रम (3) लोक परामर्श
- प्रक्रम (4) आंकलन

**I. प्रक्रम (1) - स्क्रीनिंग :**

प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, यह प्रक्रम परियोजना की प्रकृति और अवस्थिति विनिर्देश पर आधारित पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने से पूर्व उसके आंकलन के लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह अवधारण करने के लिए कि परियोजना या क्रियाकलाप के लिए आगे पर्यावरणीय अध्ययन करना अपेक्षित है या नहीं संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा प्ररूप 1 में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए किसी आवेदन की संवीक्षा होगी । कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख1" कहा जाएगा और शेष परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख2" कहा जाएगा और उसके लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी । मद 8ख के सिवाय परियोजनाओं के ख 1 या ख2 में प्रवर्गीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

**II. प्रक्रम (2) विस्तारण :**

(i) उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति, और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार और/या आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के विस्तार, सौपे जाने वाले विस्तृत और व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए, उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, आवेदन सम्मिलित हैं । विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप 1क में दी गई जानकारी के आधार पर सौंपे जाने वाले कार्य अवधारित करेगी, जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा सौंपे जाने वाले प्रस्थापित कार्य, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी सब ग्रुप द्वारा देखा गया कोई स्थल, यदि विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कार्य और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हो, सम्मिलित हैं । अनुसूची की मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/वाणिज्यिक काम्प्लैक्स/आवासन) के लिए विस्तार अपेक्षित नहीं होगा और उनका आंकलन प्ररूप 1/प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) सौंपे गए कृत्यों को प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवेदक को प्रेषित किया जाएगा । अनुसूची के प्रवर्ग क हाइड्रोक्लेक्ट्रिक परियोजना मद 1 (ग) (i) के मामले में सौंपे गए कृत्यों को पूर्व संनिर्माण क्रियाकलापों के लिए अनापत्ति सहित प्रेषित किया जाएगा । यदि सौंपे गए कृत्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाता है तो आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कृत्य ईआईए अध्ययन के लिए अनुमोदित अंतिम सौंपे गए कृत्यों के रूप में समझे जाएंगे । अनुमोदित सौंपे गए कृत्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

(iii) इसी प्रक्रम पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिश पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदनों को नामंजूर किया जा सकेगा । ऐसे नामंजूर किए जाने की दशा में, विनिश्चय को उसके कारणों सहित आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

**III प्रक्रम (3) लोक परामर्श**

(i) "लोक परामर्श" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की चिंताओं को, जिनका परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघातों में न्यायसंगत आधार है, समुचित रूप में अभिकल्पित परियोजना या क्रियाकलाप में संबंधित सभी सामग्री को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा । सभी प्रवर्ग " क" और प्रवर्ग "ख1" परियोजनाएं या क्रियाकलाप निम्नलिखित के सिवाय लोक परामर्श करेंगे :-

(क) सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण (अनुसूची की मद 1(ग) (ii))।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों के भीतर अवस्थित सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप (अनुसूची की मद 7(ग)) और जिन्हें ऐसे अनुमोदन में अननुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(ग) सड़कों और राजमार्गों का विस्तार (अनुसूची की मद 7(च))जिनमें भूमि का कोई और अर्जन अंतर्वलित नहीं है ।

(घ) सभी भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और नगरीय योजनाएं (मद 8)।

(ङ) सभी प्रवर्ग ख 2 परियोजनाएं और क्रियाकलाप ।

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप या जिसमें अन्य युक्तगत विचार अंतर्वलित हैं ।

(ii) लोक परामर्श में साधारणतया दो घटक समाविष्ट होंगे :-

(क) स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को सुनिश्चित करने के लिए परिशिष्ट 4 में विहित रीति में की जाने वाली स्थल पर या उसके निकट परिसर में जिला वार कोई लोक सुनवाई ;

(ख) परियोजना या क्रियाकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना ।

(iii) स्थल (स्थलों) पर या उसके निकट परिसर में सभी मामलों में लोक सुनवाई विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की जाएगी और कार्यवाहियों को आवेदक से प्राप्त अनुरोध के पैंतालीस दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा ।

(iv) यदि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई नहीं करती है और लोक सनुवाई को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं करती है और/या लोक सुनवाई की कार्यवाहियां को विहित अवधि के भीतर यथाउपर्युक्त संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रेषित नहीं करती है तो विनियामक प्राधिकरण अन्य लोक अभिकरण या प्राधिकरण को, जो विनियामक प्राधिकरण का अधीनस्थ नहीं है, प्रक्रिया को पैंतालीस दिनों की और अवधि के भीतर पूरा करने के लिए लगाएगी ।

(v) यदि ऊपर उपपैरा (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट लोक अभिकरण या प्राधिकरण, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को यह रिपोर्ट करता है, कि स्थानीय अवस्थिति के कारण लोक सुनवाई करना संभव नहीं है, तो किसी रीति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए जाने वाले संबंधित स्थानीय व्यक्तियों के विचारों का समर्थन करेंगे । वह उस तथ्य की रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण को ब्यौरेवार देगा जो रिपोर्ट पर और अन्य विश्वसनीय सूचना पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, जिसका लोक परामर्श के लिए विनिश्चय किया गया है, उस दशा में जिसे लोक सुनवाई में सम्मिलित करने की आवश्यकता है, रिपोर्ट करेगा ।

(vi) परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रक्रिया अभिप्राप्त करने के लिए, संबंधित विनियामक प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक द्वारा परिशिष्ट 3क में दिए गए प्ररूप में तैयार की गई संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट को उनके वेबसाइट पर देते हुए ऐसे संबंधित व्यक्तियों से लोक सुनवाई की व्यवस्था के लिए किसी लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेंगी । गोपनीय सूचना, जिसके अंतर्गत प्रकट न करने योग्य या विधिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त सूचना, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्वलित हैं, आवेदन में विनिर्दिष्ट स्रोत, वेबसाइट पर नहीं रखे जाएंगे । संबंधित विनियामक प्राधिकरण, परियोजना या क्रियाकलाप की बाबत विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य समुचित मीडिया का उपयोग भी कर सकेगा । विनियामक प्राधिकरण, तथापि लोक सुनवाई की तारीख तक निरीक्षण के लिए प्रारूप ईआईए रिपोर्ट किसी संबंधित व्यक्ति से, सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान अधिसूचित स्थान पर किसी लिखित अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा । इस लोक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त सभी प्रतिक्रियाएं शीघ्रतम उपलब्ध साधन से आवेदक को अग्रेषित की जाएंगी ।

(vii) लोक परामर्श पूरा करने के पश्चात्, इस प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त सभी सारवान पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करेगा और प्रारूप ईआइए और ईएमपी में समुचित परिवर्तन करेगा । इस प्रकार तैयार की गई अंतिम ई आई ए रिपोर्ट आवेदक के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । आवेदक, लोक परामर्श के दौरान अभिव्यक्त की गई सभी चिंताओं को संबोधित करते हुए, प्रारूप ईआईए और ईएमपी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट अंनुकल्पतः प्रस्तुत करेगा ।

**IV प्रक्रम(4) - आंकलन :**

(i) आंकलन से आवेदन और अन्य दस्तावेजों, ऐसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्शों का निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाहियां हैं, पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विस्तृत संवीक्षा अभिप्रेत है । यह आंकलन विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा किसी कार्यवाही को, जिसमें आवेदक को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रुप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, एक पारदर्शी रीति में किया जाएगा । इस कार्यवाही के निष्कर्ष पर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित निबंधनों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए उसके कारणों सहित स्पष्ट सिफारिशें करेंगी ।

(ii) सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन जो लोक परामर्श के लिए अपेक्षित नहीं है या कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, जैसा लागू हो विहित आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के आधार पर उपलब्ध सभी अन्य सुसंगत विधिमान्य सूचना और दौरा किए स्थल को, जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, कार्यान्वित किया जाएगा ।

(iii) किसी आवेदन का आंकलम, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति या प्ररूप 1 या प्ररूप 1क के साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जहां लोक परामर्श आवश्यक नहीं है, वहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अगले पन्द्रह दिनों के भीतर अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा । आंकलन की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट V में दी गई है ।

**7. (ii) विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया,-**

उस क्षमता के परे जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की गई है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या तो पट्टा क्षेत्र या खनन परियोजनाओं की दशा में उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित अंतिम सीमा के परे कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित विद्यमान यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए, प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के माध्यम से या उत्पाद मिश्रण में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित करने वाले सभी आवेदन प्ररूप 1 मे किए जाएंगे और उन पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा साठ दिनों के भीतर विचार किया जाएगा, जो सम्यक् आवश्यक तत्परता से जिसके अंतर्गत ईआईए का तैयार किया जाना और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेगी और आवेदन का तद्नुसार पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए आंकलन किया जाएगा ।

**8. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर किया जाना या उसको खारिज किया जाना,-**

(i) विनियामक प्राधिकरण, संबंधित ई ए सी या एस ई ए सी की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय को आवेदक को विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रेषित करेगा या अन्य शब्दों में अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा और जहां पर्यावरणीय समाघात निर्धारण पूरे आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर अपेक्षित नहीं है वहां अपेक्षित दस्तावेज, नीचे उपबंधित के सिवाय प्रेषित करेगा ।

(ii) विनियामक प्राधिकरण, सामान्यतः विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगा । उन दशाओं में जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों से असहमत है, वहां विनियामक प्राधिकरण विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारशों की प्राप्ति के पैंतालिस दिनों के भीतर असहमति के कारणों का कथन करते हुए पुनर्विचार का अनुरोध करेगा । इस विनिश्चय की सूचना आवेदक को साथ-साथ प्रेषित की जाएगी । उसके पश्चात् विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, विनियामक प्राधिकरण के संप्रेक्षणों पर विचार करेगी और उस पर अपने विचार साठ दिनों की और अवधि के भीतर पेश करेगी । विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अगले तीस दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाएगा ।

(iii) उस दशा में जहां विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय आवेदक को, ऊपर उपपैरा (i) या (ii) में, जहां लागू हो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसूचित नहीं किया जाता है, वहां आवेदक इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो मांगी गई पर्यावरण अनापत्ति मंजूर कर दी गई है या विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अंतिम सिफारिशों के निबंधनों में विनियामक प्राधिकरण द्वारा नामंजूर कर दी गई है ।

(iv) ऊपर पैरा (i) और (ii) के अधीन, जहां लागू हो, विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, विनियामक प्राधिकरण का विनश्चय और विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अंतिम सिफारिशें लोक दस्तावेज होंगे ।

(v) अन्य विनियामक प्राधिकरणों से परियोजनाओं या क्रियाकलापों, या संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्क्रीनिंग, विस्तारण या आंकलन या विनिश्चय पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदनों की प्राप्ति के पूर्व तब तक अपेक्षित नहीं होगी जब तक या तो ऐसी अनापत्ति किसी विधि की अपेक्षा का आवश्यक तकनीकी कारणों से कोई श्रृंखलाबद्ध आधार न हो ।

(vi) जान बूझ कर छिपाना और/या मिथ्या प्रस्तुतीकरण या भ्रामक सूचना या आंकडे देना जो स्क्रीनिंग, विस्तारण या आंकलन या आवेदन पर विनिश्चय के लिए सारवान हो, आवेदन को नामंजूर किए जाने या उस आधार पर मंजूर की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के रद्दकरण के लिए दायी बनाएगी । किसी आवेदन को नामंजूर करना या इस आधार पर पहले मंजूर की गई किसी पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के रद्दकरण का विनिश्चय विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई करने के पश्चात् किया जाएगा और उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

**9. पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता,-**

"पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता" से वह अवधि अभिप्रेत है जिससे विनियामक प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की जाती है या आवेदक द्वारा यह समझा जा सकेगा कि वह ऊपर पैरा 7 के उपपैरा (iv) के अधीन परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन प्रचालन आरंभ करने या संनिर्माण परियोजनाओं की दशा में (अनुसूची की मद 8) सभी संनिर्माण प्रचालन पूरा करने, जिसके के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए

आवेदन का निर्देश करता है, मंजूर की गई है । किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं (अनुसूची की मद 1(ग)) की दशा में दस वर्ष की अवधि के लिए, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्षों के लिए और सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में पांच वर्ष होगी । तथापि क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरीय की दशा में (मद 8(ख)) विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगी जहां तक किसी विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व है । इस विधिमान्यता की अवधि को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पांच वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि कोई आवेदन आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर किया जाता है । इस बाबत विनियामक प्राधिकरण, यथास्थिति, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति से भी परामर्श कर सकेगा ।

**10. पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानीटर करना,-**

(i) परियोजना प्रबंधन के लिए प्रत्येक कलेंडर वर्ष की 1 जून और 1 दिसंबर को संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों को अर्धवार्षिक रूप में हार्ड और साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा ।

(ii) परियोजना प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई सभी ऐसी अनुपालन रिपोर्टें लोक दस्तावेज होंगी, उसकी प्रतियां संबंधित विनियामक प्राधिकरण को आवेदन पर किसी व्यक्ति को दी जाएंगी । ऐसी अंतिम अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी दर्शित की जाएगी ।

**11. पर्यावरणीय अनापत्ति की अंतरणीयता,-**

किसी आवेदक को किसी विनिर्दिष्ट परियोजना या क्रियाकलाप के लिए मंजूर की गई कोई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अंतरक द्वारा या अंतरिकी द्वारा आवेदन पर परियोजना या क्रियाकलाप को करने के हकदार किसी अन्य विधिक व्यक्ति को अंतरक द्वारा लिखित "अनापत्ति सहित" जो इसकी विधिमान्यता की अवधि के दौरान संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आरंभ में मंजूर की गई थी और उसी विधिमान्यता अवधि के लिए अंतरित की जा सकेगी । ऐसे मामलों में विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति को कोई निर्देश आवश्यक नहीं है ।

**12. लंबित मामलों के निपटान तक ई.आई.ए. अधिसूचना का प्रवर्तन,-**

इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अधिसूचना सं0 का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, उस सीमा तक अधिक्रांत किया जाता है कि पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए किए गए और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख को लंबित सभी या कुछ प्रकार के आवेदनों को, परियोजानाओं या क्रियाकलापों को, उस सूची के सिवाय जिनमें अनुसूची 1 में पूर्व पर्यावरणी अनापत्ति अपेक्षित है, इस अधिसूचना के किसी एक या सभी उपबंधों से छूट दे सकेगी या उक्त अधिसूचना के कुछ या सभी उपबंधों के प्रवर्तन को इस अधिसूचना के जारी करने की की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जारी रख सकेगी ।

## अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखें)

**पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची**

| क्र सं. | परियोजना या क्रियाकलाप | अवसीमा सहित प्रवर्ग | | शर्तें, यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|
| | | क | ख | |
| 1 | खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1(क) | खनिज का खनन | खनन पट्टा क्षेत्र का ≥50 है0 किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐस्बेस्टज खनन | < 50 हैक्टेयर . ≥ 5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र | साधारण शर्त लागू होगी<br>टिप्पण<br>खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शत कि वास्तिवक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है । |
| 1(ख) | अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन | सभी परियोजनाएं | - | टिप्पण सार<br>खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शत कि वास्तिवक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमित ली गई है । |
| 1(ग) | नदी घाटी परियोजनाएं | (i) ≥50 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन<br>(ii)≥10,000 है0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र | (i) <50 ≥ 25 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन<br>(ii) <10,000 है0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र | सधारण शर्त लागू होगी |
| 1(घ) | तापीय विद्युत संयंत्र | (कोयला लिग्नाइट और नेप्था गैस आधारित) ≥500 मे.वा.<br>≥ 50 मे.वा.<br>(पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन ) | (कोयला/लिग्नाइट/नैफ्था एवं गैस आधारित) <500 मे.वा.<br>(पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन )<50 मे.वा ≥5 मे.वा. | साधारण शर्त लागू होगी |
| 1(ङ) | आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण | सभी परियोजनाएं | - | |
| 2 | प्राथमिक प्रसंस्करण | | | |
| 2(क) | कोयला धोवनशालाएं | ≥1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन | <1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन | साधारण शर्त लागू होगी<br>( यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2(ख) | खनिज सज्जीकरण | ≥0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन | <0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन | साधारण शर्त लागू होगी<br><br>अनापत्ति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव का खनिज सज्जीकरण के साथ ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए |
| 3 | **पदार्थ उत्पादन** | | | |
| 3(क) | धातुकर्म उद्योग (फेरस और गैर फैरस) | क ) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग<br><br>सभी परियोजनाएं<br>ख) स्पंज आयरन विनिर्माण ≥ 200 टन पी डी<br><br>ग) गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग<br><br>सभी विषाक्त और भारी धातु<br><br>उत्पादित करने वाली ईकाइयां ≥ 20,000 टन/ वार्षिक | स्पंज आयरन विनिर्माण < 200 टन पी डी<br><br>गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग<br>1) सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली ईकाइयां <20,000 टन/ वार्षिक<br>2)अन्य सभी विषरहित गौण धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग<br>> 5000 टन /वार्षिक | स्पंज आयरन विनिर्माण के लिए साधारण शर्त लागू होगी |
| 3(ख) | सीमेंट संयंत्र | वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन | वार्षिक उत्पादन क्षमता < 1.0 मिलियन टन<br>यह सभी ग्राइंडिंग इकाइयों के लिए लागू है | साधारण शर्त लागू होगी |
| 4 | **पदार्थ प्रसंस्करण** | | | |
| 4 (क) | पेट्रोलिम रिफाइनिंग उद्योग | सभी परियोजनाएं | - | - |
| 4(ख) | कोक भट्टी संयंत्र | ≥ 2,50,000 टन वार्षिक | < 2,50,000 एवं ≥ 25,000 टन वार्षिक | - |
| 4(ग) | एस्बेस्टास मिलिंग और एस्बेस्टास आधारित उत्पाद | सभी परियोजनाएं | - | - |
| 4(घ) | क्लोरक्षार उद्योग, | उत्पादन क्षमता ≥ 300टन पी डी या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से बाह्य अवस्थित ईकाई | उत्पादन क्षमता < 300 टन पी डी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित ईकाई | विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी<br><br>किसी नए पारा प्रकोष्ठ आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा झिल्लीमय प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने वाली विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 (ड़) | सोडा भस्म उद्योग | सभी परियोजनाएं | - | - |
| 4(च) | चमड़ा/त्वचा/खाल प्रसंस्करण उद्योग | औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विद्यमान ईकाइयों का विस्तार | अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित सभी नई परियोजनाएं या परियोजनाओं का विस्तार | विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी |
| 5 | उत्पादन/फैब्रिकेशन | | | |
| 5(क) | रासायनिक उर्वरक | सभी परियोजनाएं | - | - |
| 5(ख) | कीटनाशक उद्योग और कीटनाशक विशिष्ट मध्यक जीवमार (विनिर्मिति को छोड़कर) | तकनीकी श्रेणी के कीटनाशको को उत्पादन करने वाली सभी ईकाइयां | - | - |
| 5(ग) | पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश और प्राकृतिक गैस और/या सुगन्धितों में सुधार प्रसंस्करण आधारित उद्योग | सभी परियोजनाएं | - | - |
| 5(घ) | मानव निर्मित फाइवर | रेयन | अन्य | साधारण शर्त लागू होगी |
| | का उत्पादन | | | |
| 5(ङ) | पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण ( भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसर के भीतर समाविष्ट नहीं है ) | अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित | अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित | विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी |
| 5(च) | संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक; थोक औषधि और औषधि विनिर्मितियों को छोड़कर मध्यकः संश्लिष्ट रबड़ मूल कार्बनिक रसायन, अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन और रसायन मध्यक) | अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित | अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित | विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी |
| 5(छ) | आसवनी | (i) सभी शीरा आधारित आसवनी ।<br>(ii) सभी गन्ने का रस/गैर -शीरा आधारित आसवनी ≥30 कि0ली0 दैनिक | सभी गन्ने का रस/गैर शीरा आधारित आसवनी <30 कि0ली0 दैनिक | साधारण शर्त लागू होगी |
| 5(ज) | समेकित पेंट उद्योग | - | सभी परियोजनाएं | साधारण शर्त लागू होगी |
| 5(झ) | अपशिष्ट कागज से कागज का निर्माण और तैयार लुग्दी और विरंजन किए बिना तैयार लुग्दी से कागज निर्माण के अलावा लुग्दी एवं कागज | लुग्दी विनिर्माण और लुग्दी और कागज विनिर्माण उद्योग | लुग्दी विनिर्माण के बिना कागज विनिर्माण उद्योग | साधारण शर्त लागू होगी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | उद्योग | | | |
| 5(ञ) | चीनी उद्योग | | गन्ना पेरने की क्षमता ≥ 5000 टन दैनिक | साधारण शर्त लागू होगी |
| 5(ट) | प्रेरण/आर्क भट्टी/कुपोला भट्टी 5 टन प्रति घंटा या ज्यादा | - | सभी परियोजनाएं | साधारण शर्त लागू होगी |
| 6 | सेवा सेक्टर | | | |
| 6(क) | राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ प्रवाल भित्तियों/ एल एन जी टर्मिनल सहित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस परिवहन पाइप लाइनें(अपरिकृष्त और परिष्करणी /पेट्रो रसायन उत्पाद) | सभी परियोजनाएं | - | - |
| 6(ख) | एकल भंडारकरण और परिसंकटमय रसायन को संभालना (एमएसआईएचसी नियम, 1989 और 2000 की संशोधित अनुसूची 2 और 3 के स्तंभ 3 में उपदर्शित अवसीमा योजना परिमाण के अनुसार | | सभी परियोजनाएं | साधारण शर्त लागू होगी |
| 7 | पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना | | | |
| 7(क) | विमानपत्तन | सभी परियोजनाएं | - | - |
| 7(ख) | सभी पोत भंजन यार्ड जिसमें पोत भंजन इकाई भी सम्मिलित है | सभी परियोजनाएं | - | - |
| 7(ग) | औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर/ क्षेत्र/निर्यात प्रंस्संकरण जोन(नि.प्रं.जो.),विशेष आर्थिक जोन(वि.आ.जो.) जैव प्रौद्योगिकी पार्क चमड़ा परिसर | प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो<br><br>500 हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित हो | औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित है और क्षेत्र< 500 हैक्टेयर हो<br><br>औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र > 500 हैक्टेयर और जिसमें श्रेणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है | विशेष शर्त लागू होगी<br>टिप्पण<br>500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र की औद्योगिक संपदाओं जिनमें क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है, को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है |
| 7(घ) | सामान्य परिसंकटमय ,अपशिष्ट उपचार भंडारकरण और निपटान सुविधाएं (उ.भं.नि.सु.) | सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है | केवल भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं | साधारण शर्त लागू होगी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7(ङ) | पत्तन, बंदरगाह | ≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न) | <5 मिलयन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में ≥ 10,000 टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता | साधारण शर्त लागू होगी |
| 7(च) | राजमार्ग | 1) नए राष्ट्रीय राजमार्गः और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं । | 1) नए राज्य राजमार्गः और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है । | साधारण शर्त लागू होगी |
| 7(छ) | आकाशी यात्री रज्जुमार्ग | | सभी परियोजनाएं | साधारण शर्त लागू होगी |
| 7(ज) | सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्र.उ.सं.) | | सभी परियोजनाएं | साधारण शर्त लागू होगी |
| 7(झ) | नगरपालिका ठोस अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.न..अ.प्र.स.) | | सभी परियोजनाएं | साधारण शर्त लागू होगी |
| 8 | भवन/ संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण | | | |
| 8(क) | भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं | | ≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वग मीटर के निर्मित क्षेत्र # | # आवृत संनिर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र आकाश की ओर खुली सुविधाओं की दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र भी होगा । |
| 8(ख) | नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं | | ≥50हे0. क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए और या निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000 वर्ग मीटर ++ | ++ 8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ख 1 प्रवर्ग के अनुसार निबंधित किया जाएगा । |

टिप्पण

**साधारण शर्त (सा.श. )**

प्रवर्ग "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग "क " माना जाएगा, यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (iii) परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है ; और (iv) अंतरराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप सें या आंशिक रूप में अवस्थित है ।

**विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)**

यदि कोई मद 4(घ), 4(च), 5(ङ), 5(च) जैसी समयुग्म की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा/कांप्लेक्स/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमड़ा परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियों वाले उद्योग (आवश्यक नहीं कि वे समयुग्म हों) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/कांप्लेक्सों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कांप्लेक्स/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/कांप्लेक्सों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमता सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिसे कांप्लेक्स/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा) ।

[सं. जे-11013/56/2004-आईए-II(I)]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

**परिशिष्ट -I**
**(पैरा 6 देखें)**
**प्ररूप 1**

**(1) आधारभूत जानकारी**

परियोजना का नाम :

विचाराधीन अनुकल्पी अवस्थिति/स्थान :

परियोजना का आकार * :

परियोजना की प्राक्कलित लागत

संपर्क जानकारी :

संवीक्षा प्रवर्ग :

- अंचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा क्षेत्र और उत्पादन क्षमता, खनिज पूर्वेक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता )

**(II) क्रियाकलाप**

1. परियोजना का संनिर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि)

| क्र.सं. | जानकारी/जांच सूची पुष्टिकरण | हां/नहीं | उनके ब्यौरे (लगभग मात्रा/दरों, सहित, जो संभव हो, सहित) आंकड़ों की जानकारी के स्रोत सहित । |
|---|---|---|---|
| 1.1 | भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी जिसमें भूमि उपयोग की मात्रा(स्थानीय भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित है) | | |
| 1.2 | विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों की अनापत्ति | | |
| 1.3 | नई भूमि उपयोगों का सृजन | | |
| 1.4 | संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात बोर, गृह, मिट्टी का परिक्षण करना | | |
| 1.5 | संनिर्माण कार्य | | |
| 1.6 | विध्वंस कार्य | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7 | संनिर्माण कार्य या संनिर्माण कर्मकारों के घर के प्रबंध के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल | | |
| 1.8 | उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या धुस्स जिसमें अनुरेखीय संरचनाएं, काटनों और भरना या खुदाई भी सम्मिलित है। | | |
| 1.9 | भूमिगत कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना भी सम्मिलित है। | | |
| 1.10 | भूमि उद्धार कार्य | | |
| 1.11 | तलकर्षक | | |
| 1.12 | अपतट संरचनाएं | | |
| 1.13 | उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं | | |
| 1.14 | सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं | | |
| 1.15 | ठोस अपशिष्ट या तरल बहिःस्रावों के उपचार या निपटान के लिए सुविधाएं | | |
| 1.16 | परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक घर का प्रबंध के लिए सुविधाएं | | |
| 1.17 | संनिर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री यातायात | | |
| 1.18 | नई सड़क,रेल,वायु जल वाहित या अन्य परिवहन अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्ग और स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित है। | | |
| 1.19 | विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद करना या अपवर्तन या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रमुख अवसंरचना | | |
| 1.20 | नई या अपवर्तित प्रेषण लाईनें या पाइपलाइनें | | |
| 1.21 | अवरूद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनानों, पुनःरेखांकन था जलमार्गों या एक्वीफरों के जल विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन | | |
| 1.22 | प्रवाह पार | | |
| 1.23 | भूजल या भूतल से जल का अंतरण या पृथक्करण | | |
| 1.24 | नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले जलनिष्पादों या भूमि स्तर में परिवर्तन | | |
| 1.25 | संनिर्माण, परिचालन या म निकालने के लिए कार्मिक या सामग्रियों का परिवहन | | |
| 1.26 | दीर्घकालिक रूप मे तोड़ना, प्रारंभ करना या कार्य पुनः आरंभ करना। | | |
| 1.27 | आरंभ के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर समाघात कर सकेंगे। | | |
| 1.28 | जनता का किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से आना। | | |
| 1.29 | अन्य देशीय प्रजातियों का आना | | |
| 1.30 | मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की हानि | | |
| 1.31 | अन्य कोई कार्रवाईयां | | |

2. परियोजना के संनिर्माण या प्रचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग(जैसे भूमि, जल सामग्री या ऊर्जा विशेष रूप से ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं हैं या जिसका प्रदाय कम है )

| क्र.सं. | सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण | हां/नहीं | सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो) |
|---|---|---|---|
| 2.1 | विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि (हे0) | | |
| 2.2 | जल (अनुमानित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : के.एल.डी. | | |
| 2.3 | खनिज (एम.टी.) | | |
| 2.4 | संनिर्माण सामग्री -- पत्थर, औरत, बालू/मृदा (अनुमानित स्रोत एम.टी.) | | |
| 2.5 | वन और इमारती लकड़ी (स्रोत -- एम.टी.) | | |
| 2.6 | ऊर्जा जिसके अंतर्गत विद्युत और ईंधन (स्रोत, प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ऊर्जा (एम.डब्ल्यू) | | |
| 2.7 | कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (समुचित मानक इकाइयों का उपयोग करें ) | | |

3. पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग संडारण, परिवहन, उठाई धराई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिनके मानव स्वास्थ्य की जोखिम की वास्तविकता के बारे में चिंताएं उठती हैं ।

| क्र.सं. | सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण | हां/नहीं | सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो) |
|---|---|---|---|
| 3.1 | पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोरा, फौना और जल प्रदाय के लिए परिसंकटमय) (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) है | | |
| 3.2 | रोग के होने में परिवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव (उदहरणार्थ कीट या जल-जन्य रोग) | | |
| 3.3 | लोगों के कल्याण पर प्रभाव उदहरणार्थ जीवन दशाओं में परिवर्तन करके | | |
| 3.4 | लोगों के संवेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं | | |
| 3.5 | कोई अन्य कारण | | |

4. निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान ठोस अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मास)

| क्र.सं. | सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण | हां/नहीं | सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो) |
|---|---|---|---|
| 4.1 | मृदा, अधिक भार या खान अपशिष्ट | | |
| 4.2 | नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और या वाणिज्यिक अपशिष्ट) | | |
| 4.3 | परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंध तंत्र नियमों के अनुसार) | | |
| 4.4 | अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट | | |
| 4.5 | अधिशेष उत्पाद | | |
| 4.6 | मल बही-स्राव उपचार से मल गाद या अन्य गाद | | |
| 4.7 | निर्माण या ढाये गए अपशिष्ट | | |
| 4.8 | बेकार मशीनरी या उपस्कर | | |
| 4.9 | संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां | | |
| 4.10 | कृषि अपशिष्ट | | |
| 4.11 | अन्य ठोस अपशिष्ट | | |

5. वायु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विषैले या जहरीले पदार्थों का विसर्जन

| क्र.सं. | सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण | हां/नहीं | सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो) |
|---|---|---|---|
| 5.1 | लेखन सामग्री या चल संसाधनों से जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जन | | |
| 5.2 | उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन | | |
| 5.3 | सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है, उत्सर्जन | | |
| 5.4 | निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी हैं, उत्सर्जन | | |
| 5.5 | सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अपशिष्ट भी हैं, धूल या गंध | | |
| 5.6 | अपशिष्ट के भस्मीकरण से उत्सर्जन | | |
| 5.7 | खुली वायु में अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ स्क्रैप सामग्री, निर्माण सामग्री का ढेर) | | |
| 5.8 | किन्हीं अन्य स्रोतों से उत्सर्जन | | |

6. शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन

| क्र.सं. | सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण | हां/नहीं | सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो) |
|---|---|---|---|
| 6.1 | उपस्कर के प्रचालन से उदाहरणार्थ ईंजन, वातायन संयंत्र, संदलनित्र | | |
| 6.2 | औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से | | |
| 6.3 | निर्माण या ढहाने से | | |
| 6.4 | विस्फोटन या पाइलिंग से | | |
| 6.5 | निर्माण या प्रचालन संबंधी यातायात से | | |
| 6.6 | प्रकाशन या प्रशीतन प्रणालियों से | | |
| 6.7 | किन्हीं अन्य संसाधनों से | | |

7. भूमि या मल नालियों, सतही जल, भूमिगत जल, तटीय जल या समुद्र में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम

| क्र.सं. | सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण | हां/नहीं | सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो) |
|---|---|---|---|
| 7.1 | परिसंकटमय सामग्री की उठाई धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से | | |
| 7.2 | जल या भूमि में (अनुमानित ढंग और विसर्जन का स्थान) मल या अन्य बही स्रावों के विसर्जन से | | |
| 7.3 | वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से | | |
| 7.4 | किन्हीं अन्य संसाधनों से | | |
| 7.5 | क्या इन संसाधनों से पर्यावरण में प्रदूषकों के जमा होने से दीर्घकालिक जोखिम है ? | | |

8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं का जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं

| क्र.सं. | सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण | हां/नहीं | सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो) |
|---|---|---|---|
| 8.1 | परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग, भंडारण, उठाई धराई या उत्पादन से | | |
| 8.2 | किन्हीं अन्य कारणों से | | |
| 8.3 | क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-सखलन, वृष्टिस्फोट आदि) ? | | |

9. बातें जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों को करने के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थवान हैं

| क्र.सं. | सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण | हां/नहीं | सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो) |
|---|---|---|---|
| 9.1 | जिसके कारण आधार का विकास, सहायक विकास या परियोजना द्वारा विकास को बल मिलता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् –<br>• आधारिक अवसंरचना (सड़कें, बिजली प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि)<br>• आवासन विकास<br>• निष्कर्षित उद्योग<br>• पूर्ति उद्योग<br>• अन्य | | |
| 9.2 | जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है | | |
| 9.3 | पश्चात्वर्ती विकासों के लिए उदाहरण स्थापित करना | | |
| 9.4 | सामिप्य के कारण अन्य विद्यमान परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव हैं या उसी प्रकार के प्रभावों सहित नियोजित परियोजनाएं | | |

(III) पर्यावरणीय संवेदनशीलता

| क्र.सं. | क्षेत्र | नाम/पहचान | आकाशी दूरी (15 किलोमीटर के भीतर) प्रस्तावित परियोजना अवस्थान सीमा |
|---|---|---|---|
| 1. | उनके पारिस्थितिक भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अधीन संरक्षित क्षेत्र । | | |
| 2. | क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं - वेट लैड्स, जल स्रोत या अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय जोन, बायोस्फीयर, पहाड़ियां, वन | | |
| 3. | क्षेत्र जो प्रजनन, घोसला बनाने, चारे के लिए, आराम करने के लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए फ्लोरा और फोना के संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं | | |
| 4. | अंतरदेशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं | | |
| 6. | मनोरंजन की या अन्य पर्यटक/यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएं | | |
| 7. | रक्षा प्रतिष्ठापन | | |
| 8. | सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र | | |
| 9. | संवेदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोगों के अधिभोगाधीन क्षेत्र अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं | | |
| 10. | महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन, खनिज) | | |
| 11. | क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अधीन हैं (वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते हैं) | | |
| 12. | क्षेत्र जहां प्राकृतिक संकट हो सकता है जो वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं (धंसना, भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं) | | |

**परिशिष्ट 2**
**(पैरा 6 देखें)**

**प्ररूप 1क (केवल अनुसूची की मद 8 के अधीन सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए)**

**पर्यावरणीय प्रभावों की जांच सूची**

**(पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित परियोजना सलाहकार और जहां कहीं आवश्यक हो प्ररूप के साथ स्पष्टीकारक टिप्पण संलग्न करें तथा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधतंत्र योजना और मानिटरी कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत करें)**

**1. भूमि पर्यावरण**

(परियोजना स्थल और आसपास का विशाल दृश्य संलग्न करें)

1.1 क्या विद्यमान भूमि के उपयोग में परियोजना से सारवान रूप से परिवर्तन किया जाएगा जो वातावरण आसपास से संगत नहीं है ? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित मास्टर प्लान/विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए । भूमि उपयोग में परिवर्तन यदि कोई हो और सक्षम प्राधिकारी से कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए) । (i) स्थल अवस्थान, (ii) प्रस्तावित स्थल (पांच सौ मीटर के भीतर आसपास के नक्शों) और (iii) समुचित मापमान के स्थल (स्तर और समोच्च रेखा उपदर्शित करते हुए) के नक्शे संलग्न करें । यदि उपलब्ध नहीं है तो केवल अवधारणा युक्त योजना संलग्न करें ।

1.2 भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, जल उपभोग, विद्युत अपेक्षा, संयोजकता, सामुदायिक सुविधाएं, पार्किंग आवश्यकताओं आदि के अनुसार सभी बड़ी परियोजना की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें ।

1.3 प्रस्तावित स्थल से संलग्न विद्यमान सुविधाओं पर प्रस्तावित क्रियाकलाप के [illegible] खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाएं, विद्यमान भूमि उपयोग के ब्यौरे, स्थानीय पारिस्थितिकी [illegible]

1.4 क्या किसी महत्वपूर्ण भूमि विघ्न के परिणामस्वरूप भूस्खलन, [illegible] किस्म, ढाल विश्लेषण, भूमि कटाव की संवेदनशीलता, भूकंपन आदि के ब्यौरे दिए [illegible]

1.5 क्या प्राकृतिक मल निकास प्रणाली के परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव है ? (प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट प्राकृतिक मल निकासी को दर्शित करते हुए किसी समोच्च नक्शे के ब्यौरे दें)

1.6 निर्माण क्रियाकलाप — कर्तन, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वलित भूमि कार्य की मात्राएं क्या हैं ? (अंतर्वलित भूमि कार्य, स्थल आदि के बाहर से सामग्री भरने के परिवहन के ब्यौरे दें)

1.7 निर्माण अवधि के दौरान जल प्रदाय अपशिष्ट उठाई धराई आदि के संबंध में ब्यौरे दें ।

1.8 क्या नीचे के क्षेत्रों और वेट लैंडस में परिवर्तन होंगे ? (वह ब्यौरे दें कि किस प्रकार निचले क्षेत्र और वेट लैंडस प्रस्तावित क्रियाकलापों से उपांतरित हो रहे हैं)

1.9 क्या निर्माण के दौरान निर्माण के कूड़ा करकट और अपशिष्ट से स्वास्थ्य को खतरा होगा ? (निर्माण के दौरान जिसके अंतर्गत निर्माण श्रम और व्ययन की युक्तियां भी हैं, जनित अपशिष्टों की विभिन्न किस्मों की मात्राएं दें ।)

**2. जल पर्यावरण**

2.1 विभिन्न उपयोगों की अपेक्षाओं के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना के लिए जल अपेक्षा की कुल मात्रा दें । जल अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी । स्रोतों और मात्राओं का कथन करें तथा एक जल अतिशेष विवरण दें ।

2.2 जल के प्रस्तावित स्रोत की क्षमता क्या है ? (बहाव या प्राप्ति के आधार पर)

2.3 अपेक्षित जल की क्वालिटी क्या है यदि पूर्ति किसी नगर पालिक स्रोत से नहीं है ? (जल की क्वालिटी के वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक, जैव वैज्ञानिक लक्षणों को दर्शित करें)

2.4 कितनी जल अपेक्षा की उपचारित बेकार जल के पुनः चक्रण से पूर्ति हो सकती है ? (मात्राओं, स्रोतों और उपयोगिताओं के ब्यौरे दें ।)

2.5 क्या अन्य उपयोक्ताओं से जल का उपयोजन होगा ? (कृपया अन्य विद्यमान उपयोगों और उपभोग की मात्राओं पर परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करें)

2.6 प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल से प्रदूषण के भार में क्या वृद्धि है ? (प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल की मात्राओं और संघटन के ब्यौरे दें)

2.7 जल अपेक्षाओं की जल संचयन से हुई पूर्ति के ब्यौरे दें । सृजित सुविधाओं के ब्यौरें प्रस्तुत करें ।

2.8 दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरण के पश्चात् क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के लक्षणों (मात्रात्मकता के साथ-साथ क्वालिटी भी) के कारण भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा ? क्या इससे बाढ़ या जल के जमा होने की किसी रूप में समस्या में वृद्धि होगी ?

2.9 भूमिगत जल पर प्रस्ताव के क्या प्रभाव होंगे ? (क्या भूमिगत जल में नल लगाया जाएगा ; भूमिगत जल की सारणी, पुनः प्रभारण क्षमता और सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमोदन यदि कोई हों के ब्यौरे दें)

2.10 भूमि और पनिलों को प्रदूषित करने वाले निर्माण क्रियाकलापों को बंद होने से रोकने के लिए क्या सावधानियां/कदम उठाए जाने हैं ? (प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए मात्राओं और अपनाए जाने वाले उपायों के ब्यौरे दें)

2.11 स्थल के भीतर किस प्रकार तेज जल की व्यवस्था की जाएगी ? (क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए किए गए उपबंध, समोच्च स्तरों के उपदर्शन के स्थल अभिन्यास सहित उपलब्ध कराई गई जल निकासी सुविधाओं के ब्यौरे का कथन करें)

2.12 क्या आवश्यक अवधि में विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लगाए जाने से परियोजना स्थल के आसपास अस्वच्छता दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं ? (उचित स्पष्टीकरण से न्यायोचित ठहराएं)

2.13 स्थल सुविधाओं पर संग्रहण, उपचार और जल निकासी के सुरक्षित व्ययन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है ? (पुनःचक्रण और व्ययन के लिए प्रोद्योगिकी और सुविधओं सहित जनन, उपचार क्षमताओं की, चाहे जैसी हों मात्राओं के ब्यौरे दें)

2.14 दोहरी नलसाजी प्रणाली के ब्यौरे दें यदि उपयोग किए गए उपचारित अपशिष्ट का प्रसाधनों को बहाने या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है ।

**3 वनस्पति**

3.1 क्या जैवविविधता पर परियोजना का कोई खतरा है ? (स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली का उसकी विशिष्ट बातों सहित यदि कोई हों वर्णन करें)

3.2 क्या निर्माण में वनस्पति की विस्तृत निकासी या उपांतरण अंतर्वलित है ? (परियोजना द्वारा प्रभावित वृक्षों और वनस्पति का विस्तृत लेखा जोखा दें)

3.3 महत्वपूर्ण स्थल की बातों पर प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ? (किसी समुचित मापमान कि किसी अभिन्यास योजना सहित वृक्षारोपण, भूदृश्य, जल निकायों आदि के सृजन के प्रस्ताव के ब्यौरे दें)

**4. जीव जन्तु**

4.1 क्या जीव जन्तुओं, स्थलीय और जलीय रूप से किसी प्रकार हटाने या उनके चलने फिरने के लिए रूकावटें होने की संभावना है ? ब्यौरे दें ।

4.2 क्षेत्र के जीव जन्तुओं पर क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं ? ब्यौरे दें ।

4.3 जीवजन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कारीडोर, मछली सीड़ियों आदि जैसे उपाय विहित करें ।

**5. वायु पर्यावरण**

5.1 क्या परियोजना से द्वीपों में गैसों के वायुमंडलीय सांद्रण में वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप ऊष्मा बढ़ेगी ? (प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप वर्धित यातायात बढ़ने को ध्यान में रखते हुए विक्षेपण आदर्शों पर आधारित अनुमानित मूल्यों सहित पृष्ठभूमि वायु क्वालिटी स्तरों के ब्यौरे दें)

5.2 धूल, जहरीली वाष्पों या अन्य परिसंकटमय गैसों के बनने पर क्या प्रभाव हैं ? सभी मौसम विज्ञान परिमापों के संबंध में ब्यौरे दें ।

5.3 क्या प्रस्ताव से यानों को पार्क करने के स्थल में कमी आएगी ? परिवहन अवसंरचना और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों के, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल के प्रवेश और निर्गम पर यातायात व्यवस्था भी है, विद्यमान स्तर के ब्यौरे दें ।

5.4 प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों, बाइसिकिल मार्गों, पैदल यात्री मार्गों, पैदल मार्गों आदि पर चलने की पैटर्नों के ब्यौरे दें ।

5.5 क्या यातायात शोर और कंपन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ? ऊपर वर्णित बातों को कम करने के लिए स्रोतों और प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे दें ।

5.6 परियोजना स्थल के आसपास शोर स्तरों और कंपन तथा घिरी हुई वायु की क्वालिटी पर डीजी सेटों और अन्य उपस्करों पर क्या प्रभाव होगा ? ब्यौरे दें ।

6. सौन्दर्यबोद्धी

6.1 क्या प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप किसी दृश्य, दृश्यसुविधा या भूदृश्य में रूकावट होगी ? क्या प्रस्तावको ने इन बातों पर विचार कर लिया है ?

6.2 क्या विद्यमान परिनिर्माणों पर नए निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा ? किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

6.3 क्या डिजाइन मापमान को प्रभावित करने वाले शहर रूपी या शहरी डिजाइनों का कोई स्थानीय आकलन है ? उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है ।

6.4 क्या कोई मानव विज्ञान संबंधी या पुरातत्वीय स्थल या बाह्य चीजें आसपास में हैं ? कथन करें यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसपर प्रस्तावित स्थल के परिक्षेत्र में होने पर विचार किया गया है ।

7 सामाजिक - आर्थिक पहलू

7.1 क्या प्रस्ताव के परिणामस्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माणों में कोई परिवर्तन होगा ? ब्यौरे दें ।

7.2 प्रस्तावित परियोजना के आसपास विद्यमान सामाजिक अवसंरचना के ब्यौरे दें ।

7.3 क्या परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव, पवित्र स्थलों या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों में विघ्न पड़ेगा ? प्रस्तावित सुरक्षापाय क्या हैं ?

8 निर्माण सामग्री

8.1 अधिक ऊर्जा संहित निर्माण सामग्री का उपयोग हो सकेगा । क्या ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं सहित निर्माण सामग्री उत्पादित की जाती है ? (निर्माण सामग्री और उनकी ऊर्जा दक्षता का चयन करने में ऊर्जा संरक्षण उपायों के ब्यौरे दें)

8.2 निर्माण के दौरान सामग्री का परिवहन और उठाई धराई के कारण प्रदूषण, शोर और लोक अशान्ति हो सकती है । इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

8.3 क्या सड़कों और ढ़ाचों में पुनः चक्रित सामग्री उपयोग की जाती है ? की गई बचतों की सीमा का कथन करें ?

8.4 परियोजना के प्रचालन संबंधी चरणों के दौरान हुए कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और व्ययन की पद्धति के ब्यौरे दें ।

**9 ऊर्जा संरक्षण**

9.1 विद्युत अपेक्षा प्रदाय के स्रोत, स्रोत आदि की पृष्ठभूमि आदि के ब्यौरे दें । निर्मित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट ऊर्जा खपत कितनी है ? ऊर्जा खपत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

9.2 विद्युत की पृष्ठभूमि की किस्म और क्षमता, जिसको देने की आपकी योजना है, क्या है ?

9.3 उपयोग किए जाने वाले कांच के अभिलक्षण क्या हैं ? शार्ट वेव और लांग वेव विकिरण दोनों से संबंधित उसके अभिलक्षणों के निर्देश दें ।

9.4 भवन में कौन से अप्रत्यक्ष सौर वास्तविक कारक उपयोग किए जा रहे हैं ? प्रस्तावित परियोजना में किए गए उपयोजन को स्पष्ट करें ।

9.5 क्या गलियों और भवनों के अभिन्यास सौर ऊर्जा युक्तियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं ? क्या आपने भवन कम्प्लैक्स में उपयोग के लिए सड़क प्रकाशन आपात प्रकाशन और सौर तप्त जल प्रणालियों के उपयोग पर विचार कर लिया है ? ब्यौरों का सार दें ।

9.6 क्या प्रशीतन/तापन भार को कम करने के लिए शेडिंग का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है ? पूर्व और पश्चिम की दीवारों और छत पर शेडिंग को अधिकतम करने के लिए उपयोग करने के सिद्धांत क्या हैं ?

9.7 क्या परिनिर्माणों में ऊर्जा दक्ष स्थल शीतन, प्रकाशन और यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है ? तकनीकी ब्यौरे दें । ट्रांसफार्मरों और मोटर दक्षता प्रकाशन तीव्रता और वायु प्रशीतन भार धारणाओं के ब्यौरे दें । क्या आप सीएफसी एचसीएफसी फ्री चिलर्स का उपयोग कर रहे हैं ? विनिर्देश दें ।

9.8 सूक्ष्म जलवायु के परिवर्तन में भवन क्रियाकलापों के संभावित प्रभाव क्या हैं ? तप्त द्वीप और प्रतीपन प्रभावों के सृजन पर प्रस्तावित निर्माण के संभावित प्रभावों पर स्वतः निर्धारण का उल्लेख करें ।

9.9 भवन आहाते के तापीय अभिलक्षण क्या हैं ? (क) छत ; (ख) बाह्य दीवारें ; और (ग) झरोखे ? उपयोग की गई सामग्री और व्यष्टिक संघटकों के यू मूल्यों या आर मूल्यों के ब्यौरे दें ।

9.10 अग्नि संकट के लिए प्रस्तावित सावधानियां और सुरक्षा उपाय क्या हैं ? आपात योजनाओं के ब्यौरे दें ।

9.11 दिवाल सामग्री के रूप में यदि कांच का उपयोग किया जाता है तो ब्यौरे और विनिर्देश जिसके अंतर्गत उत्सर्जनता और तापीय अभिलक्षण भी हैं, दें ।

9.12 भवन में वायु प्रवेशन की दर क्या है ? प्रवेशन के प्रभावों को कैसे कम कर रहे हैं, उसके ब्यौरे दें ।

9.13 समग्र ऊर्जा खपत में अपारंपरिक ऊर्जा प्रोद्योगिकियों का किसी सीमा तक उपयोग किया जाता है ? उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रोद्योगिकियों के ब्यौरे दें ।

**10 पर्यावरण प्रबंध योजना**

पर्यावरण प्रबंध योजना में, निर्माण, प्रचालन और परियोजना के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए समस्त जीवन चक्र के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रत्येक मदवार के लिए सभी न्यूनतम करने वाले उपाय अंतर्विष्ट होंगे । इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मानिटरी योजना का आलेखन भी होगा । आपात की दशा में, जैसे स्थल पर दुर्घटना जिसके अंतर्गत आग लगना भी है, उठाए जाने वाले कदमों का कथन भी होगा ।

परिशिष्ट 3
(पैरा 7 देखें)

**पर्यावरणीय समाघात निर्धारण दस्तावेज की साधारण संरचना**

| क्र.सं. | ईआईए संरचना | अंतर्वस्तु |
|---|---|---|
| 1. | प्राक्कथन | • रिपोर्ट का प्रयोजन<br>• परियोजना और परियोजना प्रस्तावक की पहचान<br>• परियोजना की प्रकृति, आकार, अवस्थान का संक्षिप्त वर्णन और देश, प्रदेश में इसका महत्व<br>• अध्ययन का विस्तार – किए गए विनियामक विस्तार के ब्यौरे (सौंपे गए कृत्यों के अनुसार) |
| 2. | परियोजना वर्णन | • परियोजना के उन पहलुओं का संघनित वर्णन (परियोजना साध्यता अध्ययन पर आधारित) जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कारित करने की संभावना है । निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए ब्यौरे उपबंधित किए जाने चाहिए :<br>• परियोजना के किस्म<br>• परियोजना की आवश्यकता<br>• अवस्थान (साधारण अवस्थान, विनिर्दिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास को दर्शित करते हुए नक्शे)<br>• प्रचालन का आकार या विस्तार (जिसके अंतर्गत परियोजना द्वारा या उसके लिए अपेक्षित सहयोजित क्रियाकलाप)<br>• अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुसूची<br>• प्रोद्योगिकी और प्रक्रिया वर्णन<br>• परियोजना वर्णन, जिसके अंतर्गत परियोजना अभिन्यास, परियोजना आदि के संघटकों को दर्शित करते हुए आरेखन । साध्यता आरेखनों के स्कीमबद्ध प्रतिनिधित्व जो ईआईए परियोजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दें ।<br>• पर्यावरणीय मानकों, पर्यावरणीय प्रचालन दशाओं या अन्य ईआईए अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परियोजनाओं में सम्मिलित न्यूनिकरण उपायों का वर्णन (विस्तार द्वारा यथाअपेक्षित)<br>• प्रोद्योगिकीय असफलता के जोखिम के लिए नई और अपरीक्षित प्रोद्योगिकी का निर्धारण |
| 3. | पर्यावरण का वर्णन | • अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक और पद्धति<br>• विस्तार में पहचान किए गए मूल्यवान पर्यावरणीय संघटकों के लिए आधारिक लेखा की स्थापना<br>• सभी पर्यावरणीय संघटकों के आधार नक्शे |
| 4. | अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय | • परियोजना अवस्थान, संभावित दुर्घटनाओं, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालनों, पूरी की गई परियोजना को अंतिम रूप से बंद करना या पुर्नस्थापन के कारण अन्वेषित पर्यावरणीय समाघातों के ब्यौरे ।<br>• पहचान किए गए प्रतिकूल समाघातों न्यूनिकृत और/या दूर करने के लिए उपाय<br>• पर्यावरणीय संघटकों के असंपरिवर्तनीय और पुनः प्राप्त न किए जा सकने वाले आश्वासन । |

| | | |
|---|---|---|
| | | • समाघातों के महत्व का निर्धारण (महत्व महत्व निर्धारण का अवधारणा करने के लिए मानदण्ड)<br>• न्यूनीकरण उपाय |
| 5. | अनुकल्पियों का विश्लेषण (प्रोद्योगिकी और स्थल) | • यदि विस्तारित करने के कार्य के परिणामस्वरूप अनुकल्पियों की आवश्यकता होती है :<br>• प्रत्येक अनुकल्पी का वर्णन<br>• प्रत्येक अनुकल्पी के प्रतिकूल समाघातों का सार<br>• प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय और<br>• अनुकल्पी का चयन |
| 6. | पर्यावरणीय मानिटरी कार्यक्रम | • न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पद्धति, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण, रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और उपापन अनुसूचियां भी है) |
| 7. | अतिरिक्त अध्ययन | • लोक परामर्श<br>• जोखिम निर्धारण<br>• सामाजिक समाघात निर्धारण आर और आर अनुवर्ती योजनाएं |
| 8. | परियोजना के फायदे | • भौतिक अवसंरचना में सुधार<br>• सामाजिक अवसंरचना में सुधार<br>• नियोजन क्षमता - कुशल ; अर्धकुशल और अकुशल<br>• अन्य मूर्त फायदे |
| 9. | पर्यावरणीय लागत फायदा विश्लेषण | यदि विस्तारण प्रक्रम पर सिफारिश की जाती है । |
| 10. | ईएमपी | • यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनीकरण संबंधी उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और ईआईए के अनुमोदन के पश्चात् उनकी प्रभावी मानीटरी की गई है, प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन । |
| 11. | संक्षिप्त सार और निष्कर्ष (यह ईआईए रिपोर्ट का संक्षिप्त सार होगा) | • परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र औचित्य ।<br>• यह स्पष्टीकरण कि प्रतिकूल प्रभाव किस प्रकार कम किए जाते हैं |
| 12. | नियोजित परामर्शियों का प्रकटन | • उनके संक्षिप्त कार्य और दिए गए परामर्श की प्रकृति सहित नियोजित किए गए परामर्शियों के नाम. |

परिशिष्ट 3क

(पैरा 7 देखे)

**संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अंतर्वस्तु**

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संक्षिप्त सार अधिकतम ए -4 आकार के दस पृष्ठों पर पूरी पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का एक संक्षिप्त सार होगा । इसमें संक्षेप में अनिवार्य रूप से पूर्ण पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय होने चाहिएं :-

(1) परियोजना वर्णन :
(2) पर्यावरण का वर्णन :
(3) अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय :
(4) पर्यावरणीय मानीटरी कार्यक्रम :
(5) अतिरिक्त अध्ययन :
(6) परियोजना के फायदे :
(7) पर्यावरण प्रबंधन योजना :

**परिशिष्ट 4**

(पैरा 7 देखिए)

**लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया**

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध और पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।

**2.0 प्रक्रिया :**

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के परे विस्तार है तो प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक) प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :

(क) जिला मजिस्ट्रेट

(ख) जिला परिषद या नगर निगम

(ग) जिला उद्योग कार्यालय

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेषिक कार्यालय

2.3 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अपनी अधिकारिताओं के भीतर, उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे । पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार तत्परता से प्रदर्शित करेगा और दिल्ली स्थित मंत्रालय में सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी अधिसूचित स्थान पर निर्देश के लिए पूरे प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट को भी उपलब्ध करेगा ।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या पंचायतों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों अर्थात् पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट आदि को प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अतिरिक्त रूप से भी उपलब्ध कराएंगे ।

**3.0 लोक सुनवाई की सूचना**

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम से कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके ;

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेषिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;

3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य-सचिव द्वारा लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा ।

**4.0 पैनल**

जिला मजिस्ट्रेट या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।

**5.0 वीडियोग्राफी**

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय वीडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

**6.0 कार्यवाहियां**

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।

6.4 स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़ कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शित भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।

**7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि :**

7.1 लोक सुनवाई, आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी । अतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । आवेदक, लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।

7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर, किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ।

**परिशिष्ट 5**

(पैरा 7 देखिए)

**आंकलन के लिए विहित प्रक्रिया**

1. आवेदक, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए, जहां लोक परामर्श आज्ञापक है, एक सादा सूचना के माध्यम से आवेदन करेगा :-

- अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट की बीस हार्ड प्रतियां और एक साफ्ट प्रति
- लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की वीडियो टेप की एक प्रति या सी.डी.
- अंतिम अभिन्यास योजना की बीस प्रतियां
- परियोजना साध्यता रिपोर्ट की एक प्रति

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कार्यालय में तत्परता से टीओआर के प्रतिनिर्देश से समीक्षा की जाएगी और ध्यान में रखी गई अपर्याप्तताओं को प्रत्येक अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई कार्यवाहियां और प्राप्त की गई अन्य लोक प्रतिक्रियाएं भी हैं, प्ररूप 1 या प्ररूप 1क की एक प्रति और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठकों के लिए निश्चित तारीखें सहित पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्यों को एकल सेट में इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा संसूचित किया जाएगा ।

3. जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है और इसलिए कोई औपचारिक पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन अपेक्षित नहीं है, वहां आंकलन, विहित आवेदन प्ररूप 1 के आधार पर और अनुसूची की मद 8 से भिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किसी पूर्व साध्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में, इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुएं, संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, प्ररूप 1, प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें नियत करेंगी । जब कभी आवेदक सभी अन्य आवश्यक कानूनी अनुमोदनों सहित निश्चित पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों को पूरा करते हुए अनुमोदित स्कीम/भवन योजना प्रस्तुत करता है तो पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, सक्षम प्राधिकारी को पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने की सिफारिश करेगी ।

4. प्रत्येक आवेदन, पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के समक्ष और इसका पूरा आंकलन, विहित रीति में अपेक्षित दस्तावेजों/ब्यौरों सहित इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर रखा जाएगा ।

5. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की निश्चित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचित किया जाएगा ।

6. पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक के कार्यवृत्त को बैठक के पांच कार्यकरण दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । परियोजना या क्रियाकलापों को पर्यावरणीय अनापत्ति को मंजूर किए जाने के लिए सिफारिश की दशा में, कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षापायों और शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा । यदि सिफारिशें नामंजूर करने के लिए हैं तो उसके कारणों को भी स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा ।

**परिशिष्ट 6**

(पैरा 5 देखिए)

**केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए सेक्टर/परियोजना विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों की संरचना**

1. विशेषज्ञ आंकलन समितियां और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां केवल निम्नलिखित पात्रता कसौटी को पूरा करने वाले वृत्तिकों और विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी

वृत्तिक : ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम से कम (i) एम.ए./एम.एस.सी डिग्री सहित संबंधित विद्या शाखा में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या (ii) इंजीनयरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुविद विद्या शाखाओं की दशा में, बी.टेक/बी.ई./बी.आर्क. डिग्री सहित क्षेत्र में विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित किसी वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में चार वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण या (iii) अन्य वृत्तिक डिग्री (जैसे विधि) जिसमें पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित है, या (iv) विहित शिक्षुता/कारीगारी तथा संबंधित वृत्तिक संगम द्वारा संचालित परिक्षाएं उत्तीर्ण की हो (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी) या (v) किसी विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी में दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण (जैसे एम.बी.ए./आई.ए.एस./आई.एफ.एस.) व्यष्टि वृत्तकों का चयन करते समय उनके द्वारा उनके क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा ।

विशेषज्ञ : ऊपर पात्रता कसौटी को पूरा करने वाला कोई वृत्तिक जिसके पास क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का सुसंगत अनुभव या संबंधित क्षेत्र में कोई उच्चतर डिग्री हो (जैसे पी.एच.डी. और कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव) ।

आयु : सत्तर वर्ष से नीचे । तथापि, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता/कमी की दशा में विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों की अधिकतम आयु को पचहतर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों/विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे । उस दशा में कि "विशेषज्ञ" की कसौटी को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा ।

- पर्यावरण क्वालिटी विशेषज्ञ : पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप/मानिटरी, विश्लेषण और निर्वचन में विशेषज्ञ ।

- परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय विशेषज्ञ : परियोजना प्रबंधन या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया /प्रचालन/सुविधा प्रबंधन में विशेषज्ञ ।

- पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया विशेषज्ञ : पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भावी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों ।

- जोखिम निर्धारण विशेषज्ञ ।

- पेड़ - पौधे और जीव- जन्तु प्रबंधन में प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ ।

- वन और वन्य जीव विशेषज्ञ ।

- परियोजना आंकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ।

3. पर्यावरणीय निर्धारण समिति की सदस्यता पंद्रह नियमित सदस्यों से अधिक की नहीं होगी । तथापि, अध्यक्ष, समिति की किसी विशिष्ट बैठक के लिए किसी सुसंगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ।

4. अध्यक्ष, सुसंगत विकास क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और पर्यावरणीय निति या प्रबंधन में अथवा लोक प्रशासन में अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ होगा ।

5. अध्यक्ष, सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

6. पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि उसके सचिव के रूप में समिति की सहायता करेगा ।

7. किसी सदस्य की अधिकतम पदावधि, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, प्रत्येक तीन वर्ष की दो पदावधि होगी ।

8. अध्यक्ष/सदस्य को किसी कारण और समुचित जांच के बिना पदावधि के अवसान से पूर्व नहीं हटाया जा सकेगा ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2006

**S.O. 1533(E).**—Whereas, a draft notification under Sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India[1], unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environmment Policy as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006 and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union Territory Administration concerned under Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1324(E), dated the 15th September, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public ;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

---

[1]Includes the territorial waters

2. **Requirements of prior Environmental Clearance (EC):-** The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

(i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;

(ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;

(iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. **State Level Environment Impact Assessment Authority:-** (1) A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member – Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

(2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.

(3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.

(4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.

(5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.

(6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).

(7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. **Categorization of projects and activities:-**

(i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification;

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, *will* require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project;

**5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-**

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;

(b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitutes one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;

(d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;

(e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

**6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-**

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

**7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-**

**7(i)** The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

I. **Stage (1) - Screening**:

In case of Category 'B' projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity

requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project . The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

II. **Stage (2) - Scoping:**

(i) "Scoping": refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form1/Form 1A including Terms of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All projects and activities listed as Category 'B' in Item 8 of the Schedule (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities .If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

III. **Stage (3) - Public Consultation:**

(i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

(a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).

(b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.

(c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.

(d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).

(e) all Category 'B2' projects and activities.

(f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.

(ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-

(a) a public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;

(b) obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.

(iii) the public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five ) of a request to the effect from the applicant.

(iv) in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days,.

(v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which rnay, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

(vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form , within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing . Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use

other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

**IV. Stage (4) - Appraisal:**

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application be shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days .The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V ;

**7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:**

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form 1 and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence

necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

**8.Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):**

(i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.

(ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.

(iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.

(v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

(vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

**9. Validity of Environmental Clearance (EC):**

The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant - within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

**10. Post Environmental Clearance Monitoring:**

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

**11. Transferability of Environmental Clearance (EC):**

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

**12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:**

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I , or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

**SCHEDULE**

**(See paragraph 2 and 7)**

**LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE**

| Project or Activity | | Category with threshold limit | | Conditions if any |
|---|---|---|---|---|
| | | A | B | |
| 1 | | **Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)** | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1(a) | Mining of minerals | ≥ 50 ha. of mining lease area<br><br>Asbestos mining irrespective of mining area | <50 ha<br>≥ 5 ha .of mining lease area. | General Condition shall apply<br>Note<br>Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey |
| 1(b) | Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production | All projects | | Note<br>Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey |
| 1(c) | River Valley projects | (i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation;<br>(ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area | (i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation;<br>(ii) < 10,000 ha. of culturable command area | General Condition shall apply |
| 1(d) | Thermal Power Plants | ≥ 500 MW (coal/lignite/naphta & gas based);<br>≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -) | < 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based);<br><50 MW<br>≥ 5MW (Pet coke ,diesel and all other fuels ) | General Condition shall apply |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1(e) | Nuclear power projects and processing of nuclear fuel | All projects | | |
| 2 | | **Primary Processing** | | |
| 2(a) | Coal washeries | ≥ 1 million ton/annum throughput of coal | <1million ton/annum throughput of coal | General Condition shall apply<br><br>(If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal) |
| 2 (b) | Mineral beneficiation | ≥ 0.1million ton/annum mineral throughput | < 0.1million ton/annum mineral throughput | General Condition shall apply<br><br>(Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance) |

| 3 | | Materials Production | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3(a) | Metallurgical industries (ferrous & non ferrous) | a)Primary metallurgical industry<br><br>All projects<br><br>b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD<br><br>c)Secondary metallurgical processing industry<br><br>All toxic and heavy metal producing units ≥ 20,000 tonnes /annum | Sponge iron manufacturing <200TPD<br><br>Secondary metallurgical processing industry<br><br>i.)All toxic andheavymetal producing units <20,000 tonnes /annum<br><br>ii.)All other non –toxic secondary metallurgical processing industries<br><br>>5000 tonnes/annum | General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing |
| 3( b) | Cement plants | ≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity | <1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units | General Condition shall apply |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **4** | | **Materials Processing** | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4(a) | Petroleum refining industry | All projects | - | - |
| 4(b) | Coke oven plants | ≥2,50,000 tonnes/annum - | <2,50,000 & ≥25,000 tonnes/annum | - |
| 4(c ) | Asbestos milling and asbestos based products | All projects | - | - |
| 4(d) | Chlor-alkali industry | ≥300 TPD production capacityor a unit located out side the notified industrial area/ estate | <300 TPD production capacity and located within a notified industrial area/ estate | Specific Condition shall apply<br><br>No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification |
| 4(e) | Soda ash Industry | All projects | - | - |
| 4(f) | Leather/skin/hide processing industry | New projects outside the industrial area or expansion of existing units out side the industrial area | All new or expansion of projects located within a notified industrial area/ estate | Specific condition shall apply |
| **5** | | **Manufacturing/Fabrication** | | |
| 5(a) | Chemical fertilizers | All projects | - | - |
| 5(b) | Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations) | All units producing technical grade pesticides | - | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 5(c) | Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics) | All projects<br>- | - | - |
| 5(d) | Manmade fibres manufacturing | Rayon | Others | General Condition shall apply |
| 5(e) | Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes) | Located out side the notified industrial area/ estate<br>- | Located in a notified industrial area/ estate | Specific Condition shall apply |
| 5(f) | Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates) | Located out side the notified industrial area/ estate | Located in a notified industrial area/ estate | Specific Condition shall apply |
| 5(g) | Distilleries | (i)All Molasses based distilleries<br><br>(ii) All Cane juice/ non-molasses based distilleries ≥30 KLD | All Cane juice/non-molasses based distilleries<br>–<br><30 KLD | General Condition shall apply |
| 5(h) | Integrated paint industry | - | All projects | General Condition shall apply |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 5(i) | Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching | Pulp manufacturing and<br><br>Pulp& Paper manufacturing industry<br>- | Paper manufacturing industry without pulp manufacturing | General Condition shall apply |
| 5(j) | Sugar Industry | -<br>- | ≥ 5000 tcd cane crushing capacity | General Condition shall apply |
| 5(k) | Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more | -<br>- | All projects | General Condition shall apply |
| **6** | | **Service Sectors** | | |
| 6(a) | Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal | All projects<br>- | | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 6(b) | Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000) | - | All projects | General Condition shall apply |
| 7 | | **Physical Infrastructure including Environmental Services** | | |
| 7(a) | Air ports | All projects | - | - |
| 7(b) | All ship breaking yards including ship breaking units | All projects | - | - |
| 7(c) | Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes. | If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area.<br><br>Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry. | -Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha.<br><br>Industrial estates of area> 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B. | Special condition shall apply<br><br>Note:<br>Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance. |
| 7(d) | Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) | All integrated facilities having incineration &landfill or incineration alone | All facilities having land fill only | General Condition shall apply |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 7(e) | Ports, Harbours | ≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours) | < 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity | General Condition shall apply |
| 7(f) | Highways | i) New National High ways; and<br><br>ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State. | i) New State High ways; and<br><br>ii) Expansion of National / State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition. | General Condition shall apply |
| 7(g) | Aerial ropeways | | All projects | General Condition shall apply |
| 7(h) | Common Effluent Treatment Plants (CETPs) | | All projects | General Condition shall apply |
| 7(i) | Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) | | All projects | General Condition shall apply |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | | **Building /Construction projects/Area Development projects and Townships** | | |
| 8(a) | Building and Construction projects | | ≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area# | #(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area ) |
| 8(b) | Townships and Area Development projects. | | Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++ | ++All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1 |

Note:-

**General Condition (GC):**

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

**Specific Condition (SC):**

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre –defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

[No. J-11013/56/2004-IA-II(I)]
R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

## APPENDIX I

**(See paragraph – 6)**

**FORM 1**

**(I) Basic Information**

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: *

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

- *Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)*

**(II) Activity**

**1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)**

| S.No. | Information/Checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan) | | |
| 1.2 | Clearance of existing land, vegetation and buildings? | | |
| 1.3 | Creation of new land uses? | | |
| 1.4 | Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing? | | |
| 1.5 | Construction works? | | |
| 1.6 | Demolition works? | | |
| 1.7 | Temporary sites used for construction works or housing of construction workers? | | |
| 1.8 | Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations | | |
| 1.9 | Underground works including mining or tunneling? | | |
| 1.10 | Reclamation works? | | |
| 1.11 | Dredging? | | |
| 1.12 | Offshore structures? | | |
| 1.13 | Production and manufacturing processes? | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.14 | Facilities for storage of goods or materials? | | |
| 1.15 | Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents? | | |
| 1.16 | Facilities for long term housing of operational workers? | | |
| 1.17 | New road, rail or sea traffic during construction or operation? | | |
| 1.18 | New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc? | | |
| 1.19 | Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements? | | |
| 1.20 | New or diverted transmission lines or pipelines? | | |
| 1.21 | Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers? | | |
| 1.22 | Stream crossings? | | |
| 1.23 | Abstraction or transfers of water form ground or surface waters? | | |
| 1.24 | Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off? | | |
| 1.25 | Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning? | | |
| 1.26 | Long-term dismantling or decommissioning or restoration works? | | |
| 1.27 | Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment? | | |
| 1.28 | Influx of people to an area in either temporarily or permanently? | | |
| 1.29 | Introduction of alien species? | | |
| 1.30 | Loss of native species or genetic diversity? | | |
| 1.31 | Any other actions? | | |

**2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):**

| S.No. | Information/checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Land especially undeveloped or agricultural land (ha) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2 | Water (expected source & competing users) unit: KLD | | |
| 2.3 | Minerals (MT) | | |
| 2.4 | Construction material – stone, aggregates, and / soil (expected source – MT) | | |
| 2.5 | Forests and timber (source – MT) | | |
| 2.6 | Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW) | | |
| 2.7 | Any other natural resources (use appropriate standard units) | | |

**3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.**

| S.No. | Information/Checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies) | | |
| 3.2 | Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases) | | |
| 3.3 | Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions? | | |
| 3.4 | Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc., | | |
| 3.5 | Any other causes | | |

**4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)**

| S.No. | Information/Checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Spoil, overburden or mine wastes | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2 | Municipal waste (domestic and or commercial wastes) | | |
| 4.3 | Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules) | | |
| 4.4 | Other industrial process wastes | | |
| 4.5 | Surplus product | | |
| 4.6 | Sewage sludge or other sludge from effluent treatment | | |
| 4.7 | Construction or demolition wastes | | |
| 4.8 | Redundant machinery or equipment | | |
| 4.9 | Contaminated soils or other materials | | |
| 4.10 | Agricultural wastes | | |
| 4.11 | Other solid wastes | | |

**5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)**

| S.No. | Information/Checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources | | |
| 5.2 | Emissions from production processes | | |
| 5.3 | Emissions from materials handling including storage or transport | | |
| 5.4 | Emissions from construction activities including plant and equipment | | |
| 5.5 | Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.6 | Emissions from incineration of waste | | |
| 5.7 | Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris) | | |
| 5.8 | Emissions from any other sources | | |

**6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:**

| S.No. | Information/Checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data |
|---|---|---|---|
| 6.1 | From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers | | |
| 6.2 | From industrial or similar processes | | |
| 6.3 | From construction or demolition | | |
| 6.4 | From blasting or piling | | |
| 6.5 | From construction or operational traffic | | |
| 6.6 | From lighting or cooling systems | | |
| 6.7 | From any other sources | | |

7. **Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:**

| S.No. | Information/Checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data |
|---|---|---|---|
| 7.1 | From handling, storage, use or spillage of hazardous materials | | |
| 7.2 | From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge) | | |
| 7.3 | By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water | | |
| 7.4 | From any other sources | | |
| 7.5 | Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources? | | |

8. **Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment**

| S.No. | Information/Checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data |
|---|---|---|---|
| 8.1 | From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances | | |
| 8.2 | From any other causes | | |
| 8.3 | Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)? | | |

**9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality**

| S. No. | Information/Checklist confirmation | Yes/No | Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Lead to development of supporting. lities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.:<br>• Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.)<br>• housing development<br>• extractive industries<br>• supply industries<br>• other | | |
| 9.2 | Lead to after-use of the site, which could havean impact on the environment | | |
| 9.3 | Set a precedent for later developments | | |
| 9.4 | Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects | | |

**(III) Environmental Sensitivity**

| S.No. | Areas | Name/ Identity | Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary |
|---|---|---|---|
| 1 | Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests | | |
| 3 | Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration | | |
| 4 | Inland, coastal, marine or underground waters | | |
| 5 | State, National boundaries | | |
| 6 | Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas | | |
| 7 | Defence installations | | |
| 8 | Densely populated or built-up area | | |
| 9 | Areas occupied by sensitive man-made land uses *(hospitals, schools, places of worship, community facilities)* | | |
| 10 | Areas containing important, high quality or scarce resources *(ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)* | | |
| 11 | Areas already subjected to pollution or environmental damage. *(those where existing legal environmental standards are exceeded)* | | |
| 12 | Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems *(earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)* | | |

**(IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies**

## APPENDIX II

**(See paragraph 6)**

**FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)**

**CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS**

**(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)**

### 1. LAND ENVIRONMENT

**(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)**

1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii)the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.

1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).

1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).

1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)

1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)

1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.

1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)

1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

### 2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?

2.3. What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)

2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)

2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)

2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)

2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.

2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?

2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)

2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)

2.11. How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)

2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)

2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)

2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

**3. VEGETATION**

3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

**4. FAUNA**

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

**5. AIR ENVIRONMENT**

5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

**6. AESTHETICS**

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

**7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS**

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.

7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

**8. BUILDING MATERIALS**

8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)

8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?

8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?

8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

**9. ENERGY CONSERVATION**

9.1, Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?

9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?

9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?

9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.

9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.

9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?

9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.

9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?

9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

**10. Environment Management Plan**

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

## APPENDIX III

**(See paragraph 7**

**GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSENT DOCUMENT**

| S.NO | EIA STRUCTURE | CONTENTS |
|---|---|---|
| 1. | Introduction | • Purpose of the report<br>• Identification of project & project proponent<br>• Brief description of nature, size, location of the project and its importance to the country, region<br>• Scope of the study – details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference) |
| 2. | Project Description | • Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following:<br>• Type of project<br>• Need for the project<br>• Location (maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout) |

| | | |
|---|---|---|
| | | • Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project<br>• Proposed schedule for approval and implementation<br>• Technology and process description<br>• Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose<br>• Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope)<br>• Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure |
| 3. | Description of the Environment | • Study area, period, components & methodology<br>• Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope<br>• Base maps of all environmental components |
| 4. | Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures | • Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project<br>• Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified<br>• Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components<br>• Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance)<br>• Mitigation measures |
| 5. | Analysis of Alternatives (Technology & Site) | • In case, the scoping exercise results in need for alternatives:<br>• Description of each alternative<br>• Summary of adverse impacts of each alternative<br>• Mitigation measures proposed for each alternative and<br>• Selection of alternative |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Environmental Monitoring Program | • Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules) |
| 7. | Additional Studies | • Public Consultation<br>• Risk assessment<br>• Social Impact Assessment. R&R Action Plans |
| 8. | Project Benefits | • Improvements in the physical infrastructure<br>• Improvements in the social infrastructure<br>• Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled<br>• Other tangible benefits |
| 9. | Environmental Cost Benefit Analysis | If recommended at the Scoping stage |
| 10. | EMP | • Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA |
| 11 | Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report ) | • Overall justification for implementation of the project<br>• Explanation of how, adverse effects have been mitigated |
| 12. | Disclosure of Consultants engaged | • The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered |

**APPENDIX III A**
**(See paragraph 7)**

**CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT**

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report: -

1. Project Description
2. Description of the Environment
3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
4. Environmental Monitoring Programme
5. Additional Studies
6. Project Benefits
7. Environment Management Plan

## APPENDIX IV

**(See paragraph 7)**

### PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District -wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2. 0 **The Process:**

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

(a) District Magistrate/s
(b) Zila Parishad or Municipal Corporation
(c) District Industries Office
(d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz, Ministry of Environment and Forests, District Magistrate etc.

**3.0 Notice of Public Hearing:**

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member –Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

**4.0 The Panel**

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

**5.0 Videography**

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

**6.0 Proceedings**

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings.

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate ,and the SPCB or UTPCC . The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 **Time period for completion of public hearing**

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing .The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

## APPENDIX –V
**(See paragraph 7)**

**PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL**

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory: -

- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy)]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC

/SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form -1or Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal .

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule .In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle , the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance . As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

## APPENDIX VI

**(See paragraph 5)**

## COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

**Professional:** The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy ),or (v) a University degree , followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

**Expert:** A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

**Age:** Below 70 years. However, in the event of the non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality Experts**: Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality

- **Sectoral Experts in Project Management**: Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.

- **Environmental Impact Assessment Process Experts**: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process

- **Risk Assessment Experts**

- **Life Science Experts in floral and faunal management**

- **Forestry and Wildlife Experts**

- **Environmental Economics Expert with experience in project appraisal**

3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.

4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.

5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.

6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.

7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.

8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH**
**NEW DELHI**
**.....**

**MISCELLANEOUS APPLICATION NO. 1092 OF 2015**

**IN**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 478 OF 2015**

**IN THE MATTER OF:**

Vikrant Tongad
A-93, Sector-36,
Greater Noida-201308
Distt. Gautam Budh Nagar,
Uttar Pradesh

.....Applicant

Versus

1. Noida Metro Rail Corporation
Through its Chairman
Administrative Block
New Okhla Industrial Development Authority
Sector-6, Noida-201301

2. Union of India
Through its Secretary
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road
New Delhi-110003

3. State of Uttar Pradesh
Through its Secretary
Government of Uttar Pradesh
Secretariat, Lucknow-226001

4. State Environment Impact Assessment Authority
Through its Chairman
Directorate of Environment
Vineet Khand-I, Gomti Nagar
Lucknow, Uttar Pradesh

5. New Okhla Industrial Development Authority
Through its CEO
Administrative Block
Sector-6, Noida-201301
Uttar Pradesh

6. Greater Noida Development Authority
Through CEO
Chitwan Estate, GAMA II
Greater Noida 201308
Uttar Pradesh

7. Delhi Metro Rail Corporation
Through its Managing Director
Metro Bhawan, Barakhamba Road
Near Fire Station
New Delhi-110001

8. Central Ground Water Authority
Through its Member Secretary
West Block-II, Wing-3, Ground Floor
Sector-1, R.K. Puram
New Delhi - 110066

.....Respondents

**COUNSEL FOR APPLICANT:**
Mr. Rahul Choudhary, Ms. Meera Gopal, Advocates.

**Counsel for Respondents:**
Mr. Ravindra Kumar, Advocate for Respondent no. 1, 5 & 6
Mr. Raman Yadav and Mr. Abhishek Yadav, Advocates for Respondent no. 3
Mr. Abhishek Yadav, Advocate for Respondent no. 4
Mr. A.D.N. Rao and Mr. Sudipto Sircar, Advocates for Respondent No. 7
Mr. B.V. Niren, Advocate for Respondent No. 8
Mr. Krishna Kumar Singh, Advocate for MoEF

**JUDGMENT**

**PRESENT:**
**Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar (Chairperson)**
**Hon'ble Mr. Justice M.S. Nambiar (Judicial Member)**
**Hon'ble Mr. Justice Raghuvendra S. Rathore (Judicial Member)**
**Hon'ble Prof. A.R. Yousuf (Expert Member)**
**Hon'ble Mr. Bikram Singh Sajwan (Expert Member)**

**Reserved on: 17th May, 2016**
**Pronounced on: 31st May, 2016**

1. Whether the judgment is allowed to be published on the net?
2. Whether the judgment is allowed to be published in the NGT Reporter?

**JUSTICE SWATANTER KUMAR, (CHAIRPERSON)**

The applicant, who claimed to be a public spirited person and has been working in the field of environmental conservation,

particularly, devoted to conservation on wetlands and ground water for the last many years. The present application raises issues of law and procedure on the facts in relation to the construction of metro line from Noida to Greater Noida there is twofold challenge to the project, firstly, that the project has been commenced and is being carried on without obtaining prior Environmental Clearance and secondly, that the construction of the project is seriously prejudicial to the environment, ecology and also in violation of the principles stated by the Tribunal itself in various judgments including *Vikrant Kumar Tongad v. Delhi Tourism & Transportation & Ors.*

Respondent no. 1, Noida Metro Rail Corporation is executing the project, while Union of India, respondent no. 2, is the nodal agency in the administrative structure of the Central Government for the planning, promotion, co-ordination and overseeing the implementation of India's environmental and forestry policies and programmes. The primary concerns of the Ministry are implementation of policies and programmes relating to conservation of country's natural resources including its lakes and rivers, its biodiversity, forests and wildlife, ensuring the welfare of the animals and prevention and abatement of pollution.

Respondent no. 3, State of UP, is responsible for implementation of Environmental Laws and Rules within the jurisdiction of the State of UP and The State Environmental Impact Assessment Agency (for short 'SEIAA'), concerned with granting or rejecting of Environmental Compensation for the project covered

under the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (for short 'Notification of 2006'). Respondent no. 1 is in the process of construction of Metro Line from Noida to Greater Noida starting from Noida City Centre in Noida to Depot Station, Greater Noida of District Gautam Budh Nagar. The scope and area of the project can be described as follows:

| S.No. | Description | Government ($m^2$) | Private ($m^2$) | Total ($m^2$) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Land for stations | 52200.77 | 1421.9 | 53622.67 |
| 2. | Land for traction sub-station and receiving sub-station | 16000.00 | Nil | 16000.00 |
| 3. | Land for Radio Tower | 700.00 | Nil | 700.00 |
| 4. | Land for Depot | 200000.00 | Nil | 200000.00 |
| 5. | Land for running Section | 14439.34 | Nil | 14439.34 |
| | TOTAL | 283340.11 | 1421.9 | 284762.01 |

Further, the land requirement for parking of vehicles alongside the metro station is not included in this total land requirement proposed by the Respondent No. 1. The DPR of the project is made by Delhi Metro Rail Corporation. In this they have stated that the Depot of the metro rail is coming up on recreation green land, requirement for which is around 200000 sq. m. The alignment of the metro from Noida to Greater Noida also shows that it will pass through Hindon River and piers would be constructed on the river bed or flood plain.

That, during construction phase of the project, the total water requirement is about 1,40,00,000 liters. The water requirement would be met to by digging bore wells within the vicinity of the project during construction. Further, the detail Project Report (DPR) states that the water is made available by bore well within the vicinity of the project site during the construction phase. The requirement of water for operation phase is not clear for the DPR. It is submitted that the extraction of groundwater will have further impact of the depleting groundwater level of Noida and Greater Noida. Copy of the DPR is filed and annexed as Annexure A-1

That, as per the DPR 580 trees having girth size of more that 30 cm would be affected and about 478 shrubs

> would be affected by the construction of the project. It is pertinent to mention here that the DPR by DMRC for the metro rail project from Noida to Greater Noida does contain any details of rainwater harvesting system depending upon the geology of the area.
>
> That though from the DPR it is clear that the total land requirement for the project of metro rail from Noida to Greater Noida is around 284762.01 sq.m, no Environment Impact Assessment Report is Prepared.

2. The construction of tracks, stations, construction of bridge over river Hindon and other ancillary construction activities are causing dust, noise and environmental pollution. The project has been started and is being carried on without obtaining Environmental Clearance.

Different replies have been filed on behalf of the respondents. The facts are not by and large in dispute in the reply of Respondent No. 1,5 and 6, of course, it is has been specifically stated that the project does not require any Environmental Clearance within the provisions of the Notification of 2006. Further, it is disputed that the project, shall have any adverse effect on land environment, water environment, noise environment, biological environment and socio-economic either during construction or during operation. It is stated that the apprehension of the applicant is not well founded. However, respondent no. 2 has stated that under the provisions of the Notification of 2006, construction of new project or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the schedule annexed to the Notification entailing capacity addition with change in process and/or technology shall be undertaken in any part, only upon grant of prior Environmental

Clearance in terms of sub-section 3, Section 3 of the Environmental (Protection) Act, 1986 and in accordance with the procedure prescribed under Notification of 2006. This applies to all projects or activities covered under the Schedule to Notification. The railway project, metro rail project are not within the purview of the Notification of 2006.

3. Respondent no. 3 and 4 have filed a common reply. It has been submitted by way of preliminary submission that the present project is not covered under the Notification of 2006 and all the projects that are received by SEAC, Uttar Pradesh are dealt with in accordance with that Notification. It is further submitted that the illegal construction, if any, raised is not a matter that relates to the said respondent. The SEAC, Uttar Pradesh has not received as on 14th March, 2016 any application on prescribed format regarding the grant of Environmental Clearance for the project relating to construction of Metro from Noida to Greater Noida, District Gautam Budha Nagar. Therefore, the question of the grant of prior Environmental Clearance to the project proponent does not arise.

The applicant has filed a common rejoinder to the reply filed by the respondent nos. 1,2,5 and 8. In the rejoinder it is reiterated that the project has been covered under the Notification of 2006 and it requires prior Environmental Clearance for any activity to be carried on in the project. The applicant has placed reliance upon the Judgement of the Tribunal in the Case of *Vikrant Kumar Tongad v. Delhi Tourism & Transportation & Ors.*, *S.P. Muthuraman v. Union of India & Ors.* and *Himmat Singh Shekhawat v. Union of India & Ors.*

From the above pleadings and contentions raised on behalf of the parties, the following 2 issues arise for consideration of the Tribunal.

1. Whether, project in question is covered under the EIA Notification of 2006, if so, to what extent?
2. Whether activities being carried on by the Project Proponent including construction of Bridges are bound to cause environmental degradation, environmental pollution, traffic and other hazards?

4. Further if the project proponent is liable to be directed to comply with certain precautionary measures before it can carry on with its project activity any further. The first issue is bound to have its consequence on merit of issue no. 2 as well. Issue no. 1 is primarily an issue of law and needs to be determined with reference to the language of Notification of 2006. It is undisputable that if a project falls under any of the entries of Schedule 1 to the Notification of 2006 then it will be statutorily obligatory upon the project proponent to seek "Prior Environmental Clearance" for the project or activity that the project proponent intends to carry on. Grant of Environmental Clearance is a condition precedent to the commencing of any activity of the project including its escalation work. The consequences of non compliance would follow and a project proponent would not be permitted to carry on the project activity in absence of such clearance. In this background now we may examine the entries contained in Schedule 1 of the Notification of 2006.

5. Clause 2 of the Notification of 2006 requires the project or activities falling under Category A and Category B to obtain prior Environmental Clearance from the concerned Regulatory Authority, i.e. category A from Ministry of Environment, Forests & Climate Change and Category B from SEIAA if they fall under the Schedule 1 of the Notification of 2006. Schedule 1 of the Notification is a list of the project or activities requiring prior Environmental Clearance. The Environmental Clearance is to be granted strictly in accordance with the procedure prescribed and the methodology stated in the Notification of 2006. The entries in the Schedule 1 specify the project or activity, categories with threshold limit that is if project was category A and B and conditions if any upon or otherwise required to be imposed upon such a project. The present case has relied upon entry 8B of the Schedule. Building construction project/area or development projects and township projects are covered under entry 8 categorised into 8A and 8B respectively. The said entry 8 reads as follows:-

| Project or Activity | Category with threshold limit | | Conditions if any | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | | |
| 8 | Building/Construction Projects/Area Development Projects and Township | | | |
| 8(a) | Building and Construction projects | | ≥ 20000 sq mtrs and < 1,50,000 sq mtrs of bilt up area# | [The built –up area for the purpose of this notification is defined as "the built-up or covered area on all the floors put together including basement(s) and other service areas, which are |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | proposed in the building/construction projects] |
| 8(b) | Township and Area Development Projects | | Covering an area ≥50 ha and or built up area ≥ 1,50,000 sq mtrs++ | ++All projects under Item 8(b) Shall be appraised as Category B1. |

The bare reading of the above Entries of the Schedule does show that railway projects whether metro or otherwise has not been specifically mentioned in the entry. The contentions raised by the applicant before us is that these projects are covered under entry 8B of the Notification of 2006 in as much as they are development projects.

6. They would squarely fall under the Heading Township and or development projects. Where the area covered is equal to or more than 50 hectare and/or built up areas is equal to or more than 1,50,000 sq. mtr. they have to be treated as category B1 projects. According to the computation stated in the application which has not been specifically denied by any of the respondents the total land area required for the project is 2,84,762.01 sq. mtrs. which is higher to the threshold built up area and would be much in excess of 1,50,000 sq mtr as the metro track runs in miles. The entries have to be given a purposive interpretation. The interpretation which is held to achieve object has to be granted to such entries. These entries are not the entries which will require strict interpretation or strict consideration. The framers of the Notification itself have used

the terms with liberal expression and which are capable of receiving liberal interpretation.

7. It may not be necessary for us to deliberate on this issue at any greater length in view of the detailed judgment of this Tribunal in the case of *Vikrant Kumar Tongad v. Delhi Tourism and Transport Corporation* 2015 All (I) NGT Reporter (1) PB 244 directly on the issues involved in the present application. In that case, a similar contention was raised that construction of the signature bridge over River Yamuna at Wazirabad was not covered under the Notification of 2006 and, therefore, no environmental clearance was required. Larger Bench of this Tribunal while holding that the mandate of the Notification of 2006 was to protect the environment and ecology while providing for sustainable development held that without sense it would be a welfare legislation. The right to environment being a right to life within the meaning of Article 21 of the Constitution of India, adherence to the environmental laws was stated to be mandatory. It was also held that in conflict of environmental interest and economic interest, the former would prevail and due regard should be paid to the Precautionary Principle. It was finally held that the project falls under Entry 8(b) of the Notification of 2006 and the authorities were required to obtain Environmental Clearance, though the work was not stopped or demolition was not directed in that case. It will be useful to refer to the following paragraphs of the judgment:

> "18. Having deliberated upon the relevant provisions of the Regulations of 2006, now we would deal with the principles applicable to interpretations of such Entries.

The Hon'ble Supreme Court in its various judgments has stressed upon the liberal interpretation of a statute, if it is a social welfare legislation. For instance, in the case of *The Authorised Officer, Thanjavur and Anr. v. S. Naganatha Ayyar and Ors.*, (1979) 3 SCC 466, the Court held that:

> "1. While dealing with welfare legislation of so fundamental a character as agrarian reform, the court must constantly remember that the statutory pilgrimage 14 to 'destination social justice' should be helped, and not hampered, by judicial interpretation."

In the case of Workmen of American Express International Banking Corporation v. Management of American Express International Banking Corporation, (1985) 4 SCC 71, the Court held that:

> "4. The principles of statutory construction are well settled. Words occurring in statutes of liberal import such as social welfare legislation and 'Human Rights' legislation are not to be put in procrustean beds or shrunk to Liliputian dimensions. In construing these legislations the imposture of literal construction must be avoided and the prodigality of its mis-application must be recognised and reduced. Judges ought to be more concerned with the 'colour', the 'content' and the 'context' of such statutes."

In the case of *Securities and Exchange Board of India v. Ajay Agarwal*, (2010) 3 SCC 765, the Court held that:

> "41. It is a well known canon of construction that when Court is called upon to interpret provisions of a social welfare legislation the paramount duty of the Court is to adopt such an interpretation as to further the purposes of law and if possible eschew the one which frustrates it."

19. The Courts have also evoked the principle of purposive construction in relation to social welfare legislations. The statute and its provisions have to be given an expanded meaning that would tilt in favour of the object of the Act, curing or suppressing the evil by enforcing the law. While interpreting an Entry in a Schedule to an Act, the ordinary rule of construction requires to be applied to understand the Entries. There is a functional difference between a body of the statute on the one hand and the Schedule which is attached thereto on the other hand. The Sections in these 15 Acts are enacting provisions. In contrast, the Schedule in an Act sets down things and objects and contains their names and descriptions. The sections of and the Schedule to the Act, have to be co-jointly read and construed, keeping in view the purpose and object of the Act while keeping a clear distinction between a fiscal and a social welfare legislation in mind. Social

welfare programmes projected by the State and object of the statute are of paramount consideration while interpreting and construing such Entries. The law is always intended to serve the larger public purpose. In fact, welfare of the people is the supreme law and an enacted law should be administered lawfully, i.e., salus populi est suprema lex. It is not possible even for the legislature to comprehend and provide solution to all the evils or obstacles that are likely to arise in implementation of the enacted laws. Therefore, the Tribunal must adopt an approach for interpretation of these Entries which would further the cause of the Act and the intent of the legislation and be not unduly influenced by the rule of restricted interpretation.

XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

25. Thus, the assessment of such impact and degradation of environment resulting therefrom, is essential and is a matter which is of concern for the Expert Bodies appointed under the Act. Furthermore, Environmental Impact Assessment Guidance Manual for Building, Construction, Township and Area Development Project, 2010 provides that environmental facets which are to be considered in relation to township and area development are land, air, noise, water, biological, socio-economic and solid waste management. Thus, it is necessary to ascertain the baseline data of these environmental facets before a project or an activity may be permitted or carried out.

26. The Regulations of 2006 have been promulgated with the aim and object of assessing the impact that a project or an activity would have upon the environment and ecology. The expert body is expected to precisely visualise the extent of environmental degradation resulting from the project before granting approval. Normally, the projects having irretrievable and permanent impacts on nature are not permitted, and where permitted, very stringent, protective and precautionary conditions are imposed. Thus, it is relevant at this stage to understand the concept of EIA as contemplated under the Regulations of 2006 with reference to the 20 provisions of the Act of 1986 for protection of ecology and biodiversity of the river and riverbed.

27. In order to understand the concept of EIA, one first needs to know what an 'Environmental Impact' is. An 'Environmental Impact' is any impact or effect (positive or negative) that an activity has on an environmental system, environmental quality or natural resources. It is also known as an environmental effect [Oxford Dictionary of Environment and Conservation, First Edn., 2007]. An 'Environmental Effect' is defined as a natural or artificial disturbance of the physical,

chemical or biological components that make up environment [Black's Law Dictionary, 9th Edn., 2009]. Such activities may take the form of mining, oil and gas exploration, thermal, nuclear and hydraulic power plants, metallurgical industries, chemical fertilizers, storing of hazardous chemicals, industrial estates/parks/complexes/areas, waste treatment plants, etc.

28. EIA was first introduced in the USA in 1969 and has since been widely accepted. It is being adopted in one form or the other in an increasing number of countries as a basis for making informed and rational judgments about what sort of developments are environmentally acceptable. It even includes the concept of 'Strategic Environmental Assessment'. An EIA is defined as a formal statement of the environmental impacts that are likely to arise from major activities such as new legislation or a new policy, programme or project. The results of the assessment are reported in the 21 'Environment Impact Statement' (EIS) [Oxford Dictionary of Environment and Conservation, First Edn., 2007]. Thus, an EIA in general parlance does not confine itself only to projects but also to legislations and policies.

29. With expansion and modernization of economic and trade activities in India, there was a need felt to understand as well as regulate the potential environmental impacts that such activities may have. Thus, in order to impose certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on expansion or modernization of existing projects or activities, the Central Government enacted the Environment Clearance Regulations, 2006, on 14th September, 2006 under Section 3(1) and 3(2)(v) of the Act of 1986 and Rule 5(2) of Rules of 1986. The objective of the Regulations of 2006 is to set procedures of environmental clearance before establishment of project of identified nature and size. It required the construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the notification to be undertaken in any part in India only after prior Environmental Clearance is granted by the particular authority. These Regulations do not define an EIA or an EIS. However, it requires the Expert Appraisal Committees in case of category 'A' projects and the State Level Expert Appraisal Committees in case of category 'B-1' projects or activities, including applications for expansion and modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, to determine detailed and comprehensive ToR addressing all relevant environmental 22 concerns for

the preparation of an EIA. Categorization of projects/activities into category 'A' or 'B' is done on the basis of the potential hazards that it poses to the environment, location, the extent of area involved etc.

30. Thus, clearly, the mandate of the Regulations of 2006 is to ensure protection of environment and ecology in face of rapid developmental activities, which are even the need of the hour. Since the object of the Regulations of 2006 is to provide developmental activities while ensuring presence of a safer environment, it can be termed as welfare legislation. Thus, the rule of reasonable constructions in conjunction with the liberal construction would have to be applied. Article 48A in Part-IV (Directive Principles) of the Indian Constitution enjoins that "State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country". Article 47 further imposes a duty on the State to improve public health as its primary duty. Article 51A(g) imposes "a fundamental duty" on every citizen of India to protect and improve the natural "environment" which includes forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures. The word "environment" is of broad spectrum which brings within its ambit "hygienic atmosphere and ecological balance". It is, therefore, not only the duty of the State, but also the duty of every citizen to maintain hygienic environment. The State, in particular, has a duty in that behalf to shed its extravagant, unbridled sovereign power 23 and to forge in its policy, to maintain ecological balance and hygienic environment. Article 21 protects 'Right to Life' as a fundamental right. Enjoyment of life and its attainment, including the right to live with human dignity, encompasses within its ambit, the protection and preservation of environment, ecological balance, free from pollution of air and water, sanitation, without which life cannot be enjoyed. Any contra acts or actions would cause environmental pollution. Therefore, there is a constitutional imperative on the State authorities and bodies like the Pollution Control Board not only to ensure and safeguard proper environment, but also to take adequate measures to promote, protect and improve the environment, both, man-made and natural. Sections 3 and 5 of the Act of 1986, apart from other provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, empower the Government to make all such directions and take all such measures as are necessary or expedient for protecting and promoting the 'Environment', which expression has been defined in very wide and expansive terms in Section 2(a) of the Act

of 1986. [*Noyyal River Ayacutdars Protection Association rep. by its President, P.M. Govindaswamy Pappavalasu v. The Government of Tamil Nadu rep. by its Secretary, Public Works Department and Ors.*, 2007-1-LW 275, *Indian Council for Enviro-Legal Action etc. v. Union of India*, (1996) 3 SCC 212]. The flood plains and river bed of Yamuna are under increasing pressure of alternative land use for various purposes, which are 24 driven primarily by growth of economy at the cost of the river's integrity as an eco-system. [*Manoj Mishra v. Union of India*, Original Application No. 6 of 2012 and Original Application No. 300 of 2013, decided on 13th January, 2015]. The powers conferred on the Central Government by virtue of provisions contained in Section 3, 5 and 25 of the Act of 1986 and on the National Green Tribunal by virtue of Sections 14, 15 and 16 read with Section 18 of the National Green Tribunal Act, 2010, are wide enough to provide for protection, preservation and restitution of the environment and ecology of the river bed of River Yamuna.

31. If an activity is allowed to go ahead, there may be irreparable damage to the environment and if it is stopped, there may be irreparable damage to economic interest. In case of doubt, however, protection of environment would have precedence over the economic interest. Precautionary principle requires anticipatory action to be taken to prevent harm. The harm can be prevented even on a reasonable suspicion. It is not always necessary that there should be direct evidence of harm to the environment [*Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India,* (1996) 5 SCC 647].

32. The applicability of 'Principle of Liberal Construction' to socio-welfare legislation like the Act of 1986, thus, could be justified either with reference to the 'doctrine of reasonable construction' and/or even on 'constructive intuition'. In the case of *Haat Supreme Wastech Pvt. Ltd. v. State of Haryana and Ors*, 2013 ALL (I) NGT REPORTER (2) (DELHI) 140, the Tribunal, while dealing with 25 interpretation of the Regulations of 2006 along with the Schedule and while deciding whether the bio-medical waste disposal plants required Environmental Clearance or not, answered the question in affirmative, that, such plants are covered under Entry 7(d) and while answering so, applied the doctrine of 'reasonable construction' as well as 'constructive intuition'. Doctrine of 'reasonable construction' is intended to provide a balance between development and the environment. The Tribunal held that there was no occasion for the Tribunal to take the scope of Entry 7(d) as unduly restrictive or limited and it gave the entry a wide meaning. It was also held that the Environmental Clearance would help in ensuring a critical analysis of

the suitability of the location of the bio-medical waste disposal plant and its surroundings and a more stringent observation of parameters and standards by the project proponent on the one hand and limiting its impact on public health on the other.

33. 'Development' with all its grammatical variations, means the carrying out of building, engineering, mining or other operations in, on, over or under land or the making of any material change in any building or land and includes re-development. It could also be an activity, action, or alteration that changes underdeveloped property into developed property (Ref: Wharton's Law Lexicon, 15th Edn., 2012, Black's Law Dictionary 9th Edn., 2009). Reading of Clause 2 of the Regulations of 2006 and the Schedule attached thereto, particularly in light of the above principles, clearly demonstrates that an expression of very wide magnitude has been deliberately 26 used by the framers. They are intended to cover all projects and activities, in so far as they squarely fall within the ambit and scope of the Clause. There does not appear to be any interest for the Tribunal to give it a narrower or a restricted meaning or interpretation. In the case of *Kehar Singh v. State of Haryana*, 2013 ALL (I) NGT REPORTER (2) (DELHI) 140, the Tribunal had specifically held that there should exist a nexus between the act complained of and environment and that there could be departure from the rule of literal construction, so as to avoid the statute becoming meaningless or futile. In case of a social or beneficial legislation, the Tribunal should adopt a liberal or purposive construction as opposed to the rule of literal construction. The words used therein are required to be given a liberal and expanded meaning. The object and purpose of the Act of 1986 and the Schedule of Regulations of 2006 thereto was held to be of utmost relevance. In the case of present kind, if no checks and balances are provided and expert minds does not examine and assess the impacts of such projects or activities relating to development, consequences can be very devastating, particularly environmentally. Normally, the damage done to environment and ecology is very difficult to be redeemed or remedied. Thus, a safer approach has to be adopted to subject such projects to examination by Expert Bodies, by giving wider meaning to the expressions used, rather than to frustrate the object and purpose of the Regulations of 2006, causing irretrievable ecological and environmental damage.

34. There can hardly be any escape from the fact that Entries 8(a) and 8(b) are worded somewhat ambiguously. They lack certainty and definiteness. This

was also noticed by the Hon'ble Supreme Court in the case of In Re: Construction of Park at Noida Near Okhla Bird Sanctuary v. Union of India (UOI) & Ors., (2011) 1 SCC 744, where the Court felt the need that the Entries could be described with greater precision and clarity and the definition of 'built-up area' with facilities open to the sky needs to be freed from its present ambiguity and vagueness. Despite the above judgment of the Hon'ble Supreme Court, Entry 8(a) and 8(b) were neither amended nor altered to provide clarity or certainty. However, the expression 'built up area' under the head 'conditions if any' in column (5) of the Schedule to the Regulations of 2006, was amended vide Notification dated 4th April, 2011. Dehors the ambiguities in these Entries, an interpretation that would frustrate the object and implementation of the relevant laws, would not be permissible. 'Township and Area Development project' is an expression which would take within its ambit the projects which may be specific in relation to an activity or may be, they are general Area Development projects, which would include construction and allied activities. 'Area Development' project is distinct from 'Building and Construction' project, which by its very language, is specific and distinct. Entries 8(a) and 8(b) of the Schedule to the Regulations of 2006 have been a matter of adjudication and interpretation before the Hon'ble Supreme Court in the case of In Re: *Construction of Park at Noida Near Okhla Bird Sanctuary v. Union of India (UOI) & Ors.*, (supra). In that case, Hon'ble Supreme Court was concerned with the construction of a park in Noida near the Okhla Bird Sanctuary. The Hon'ble Supreme Court provided a distinction between a 'Township project' and 'Building and Construction project' and held that a 'Township project' was different, both quantitatively and qualitatively from a mere 'Building and Construction project'. Further, that an Area Development project may be connected with the Township Development project and may be its first stage when grounds are cleared, roads and pathways are laid out and provisions are made for drainage, sewage, electricity and telephone lines and the whole range of other civic infrastructure, or an area development project may be completely independent of any township development project as in the case of creating an artificial lake, or an urban forest or setting up a zoological or botanical park or a recreational, amusement or a theme park. The Hon'ble Supreme Court principally held that a zoological or botanical park or a recreational park etc. would fall within the category of Entry 8(b) but, if it does not specify the threshold marker of minimum area, then it may have to

be excluded from operation of the mandatory condition of seeking prior Environmental Clearance. The Court held as under:

"66. The illustration given by Mr. Bhushan may be correct to an extent. Constructions with built up area in excess of 1, 50,000 sq mtrs. would be huge by any standard and in that case the project by virtue of sheer magnitude would qualify as township development project. To that limited extent there may be a quantitative correlation between items 8(a) and 8(b). But it must be realized that the converse of the illustration given by Mr.Bhushan may not be true. For example, a project which is by its nature and character an *"Area Development project" would not become a "Building and Construction project"* simply because it falls short of the threshold mark under item 8 (b) but comes within the area specified in item 8 (a). The essential difference between items 8(a) and 8(b) lies not only in the different magnitudes but in the difference in the nature and character of the projects enumerated there under.

67. In light of the above discussion it is difficult to see the project in question as a "Building and Construction project". Applying the test of 'Dominant Purpose or Dominant Nature' of the project or the "*Common Parlance" test, i.e. how a common person using it and enjoying its facilities would view it, the project can only be categorized under item 8(b) of the schedule as a Township and Area Development project*". But under that category it does not come up to the threshold marker inasmuch as the total area of the project (33.43 hectares) is less than 50 hectares and its built-up area even if the hard landscaped area and the covered areas are put together comes to 1,05,544.49 square metres, i.e., much below the threshold marker of 1,50,000 square metres."

35. Besides dealing with the scope and dimensions of Entries 8(a) and 8(b) of the Schedule afore-stated, the Hon'ble Supreme Court, while referring to the findings given by the CEC in its report, that the Project was located at a distance of 50 mtrs. from the Okhla Bird Sanctuary and that in all probability, the project site would have fallen in the Eco-Sensitive Zone had a timely decision in this regard being taken by the State Government/MoEF, permitted continuation of the project, and held as under:

"74.The report of the CEC succinctly sums up the situation. Though everyone, excepting the project proponents, views the construction of the project practically adjoining the bird sanctuary as a potential hazard to the sensitive and fragile ecological balance of the Sanctuary there is no law

to stop it. This unhappy and anomalous situation has arisen simply because despite directions by this Court the authorities in the Central and the State Governments have so far not been able to evolve a principle to notify the buffer zones around Sanctuaries and National Parks to protect the 30 sensitive and delicate ecological balance required for the sanctuaries. But the absence of a statute will not preclude this Court from examining the project's effects on the environment with particular reference to the Okhla Bird Sanctuary. For, in the jurisprudence developed by this Court Environment is not merely a statutory issue. Environment is one of the facets of the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution"

36. The above dictum of the Supreme Court clearly laid down a fine distinction between Entries 8(a) and 8(b) of the Schedule to the Regulations of 2006 on one hand, while on the other hand held that mere absence of law cannot be a ground for degrading the environment, as environment is one of the facets of 'Right to Life' as envisaged under Article 21 of the Constitution of India.

37. Thus, this Tribunal has to examine the ambit and scope of Entry 8(b) while keeping in mind the Scheme and Object of the Act of 1986, the Rules of 1986, the Regulations of 2006 along with its Schedule and most importantly right to clean environment as an integral concept of our Constitutional Scheme. The project in question is construction of a 'Signature Bridge' over River Yamuna, connecting eastern and western ends of the city of Delhi and to ensure fast and smooth flow of traffic in that part of the city. This certainly is an Area Development project falling within Entry 8(b) of Schedule to the Regulations of 2006. There is also no dispute that the total constructed area of the 'Signature Project' is 1,55,260 sq. mtrs., which is higher than the threshold marker of 1,50,000 sq. mtrs. This project cannot fall within Entry 7(f) of the Schedule to 31 the Regulations of 2006, as it is neither a national nor a city highway and not even any part thereof.

38. Having held that the project in question is covered under Entry 8(b) of the Schedule to the Regulations of 2006, now we have to consider what relief can be granted to the applicant in the facts and circumstances of the case. Admittedly, particularly according to the Project Proponent, various other departments have granted them clearances and/or have already issued No Objection Certificates for construction of the said project. MoEF vide its letter dated 14th March, 2007 had informed the Project Proponent that 'bridges' are not covered under the Regulations of 2006 and as such, no prior Environment Clearance was required for

> commencement of the project. It is in the backdrop of these circumstances that the construction of the project commenced in the year 2007. As of today, more than 80 per cent of the bridge has already been completed. Huge public funds have been spent on this project. It is intended to serve public purpose and is in public interest, namely free and fast flow of traffic between east and west Delhi. Apparently, we cannot attribute any fault or breach of legal duty to the Project Proponent (Respondent No. 1). We do not think it is a case where we should either direct stoppage of project work or direct demolition thereof"

8. From the above paragraphs, it is evident that the construction of the bridge over a River was not specifically stated in any of the Entries of the Notification of 2006. The object of the Notification would stand defeated if such huge constructions which admittedly falls much above the threshold limits of construction prescribed under the Notification of 2006, are exempted or held to be not covered under the Notification.

The framers in their wisdom used two different expressions 'Township' and 'Area Development Projects'. The expression 'and' used in Entry 8(b) would have to be read as disjunctive between 'Township' and 'Area Development Projects'. They cannot be read as synonyms. Development projects could be *de hors* of a township while township may take in its ambit a development project in general. In the present case, the project includes use of land for construction of stations, traction sub-stations, receiving stations, land for radio towers, for depot and for running station section. The total land required, as already noticed, is 2,84,762.01 sq. mtrs. and the construction to be raised upon this land is much above the threshold limit of 1,50,000 sq. mtrs. The applicant has also placed on record a copy of the detailed project report. In this report, the

details of the project have been stated. Information like result of soil analysis, water resources, chemical analysis of water samples and matter in relation to noise, water and air pollution have been dealt with as well as environmental costs have been prescribed. The project specifies land requirement for stations, tractions and receiving sub-stations, radio towers, land for depot running stations and for temporary construction. The applicant has also emphasized upon extraction of ground water for construction and project purposes and requisite permission from the Central Ground Water Board has not been taken. The construction details clearly demonstrate huge construction and large scale requirement of land, which is definitely beyond the threshold limits specified under the Notification.

9. The purpose of the Notification of 2006 is not to prohibit development but to permit the same while protecting the environment and ecology. It is the requirement that there should not be irretrievable or irreversible damage to the nature and environment. In the event the project commenced damage then the entire project would fall beyond the known dimensions of principle of Sustainable Development and would apparently result in violation of Pre-cautionary Principle. Unchecked and indiscriminate development would certainly have adverse impacts upon the environment and ecology of the area. The learned counsel appearing for the respondents have not brought to our notice any judgment taking a view contrary to the view taken in the judgment of this Tribunal in the case of *Vikrant Kumar Tongad* (supra).

Taking environmental clearance would cause no prejudice to any of the stakeholders on the one hand, while on the other it will protect the environment, nature, the river and its banks. The official respondents and the project proponents both had been ad idem that the project did not require prior Environmental Clearance in terms of Notification of 2006. Since we have now held that the project is covered under the Notification of 2006, therefore, it will be obligatory on the part of the project proponent to take Environmental Clearance.

10. In these circumstances, we do not consider it appropriate to impose environmental compensation upon the project proponent subject to the condition that it will carry out and comply with all the terms and conditions that would be now imposed by SEIAA as it is Category-B1 project.

The entire matter would have to be examined by SEIAA and they would have to impose conditions which would direct corrective measures that the project proponent is required to take as well as the conditions which it should comply with in future in the aid of Precautionary Principle, in the interest of the nature, environment and ecology.

In view of our finding on Issue No.1, it is not necessary for us to deliberate upon and decide upon Issue No.2. As a consequence of our finding on Issue No.1, it would squarely fall in the domain of SEIAA which will deal with all the aspects of protection of environment and ecology and place such restrictions upon the project as it may deem fit and proper.

11. In view of the above discussion, we dispose of this application with the following directions:-

1. We hold and declare that the project in question, that is, the Metro Construction from Noida to Greater Noida is a project covered under Entry 8(b) of the Schedule to the Notification of 2006.
2. We direct the respondent no.1, the project proponent to obtain Environmental Clearance for the project in question as expeditiously as possible and in any case not beyond three months from the date of pronouncement of this judgment. The application in Form 1A shall be submitted within one week from today to SEIAA, Uttar Pradesh. It shall dispose of the application as Category B-1 project as expeditiously as possible, and in any case, not later than the period aforestated.
3. SEIAA shall impose conditions, both in regard to the remedial measures as well as for completion of the project in terms of the Notification of 2006 and protection of the environment and ecology in that area.
4. We make it clear that if the work already executed by the project proponent has caused any irretrievable loss to environment, ecology and nature, the SEIAA would be well within its rights even to direct demolition of such constructed portion.

5. The order granting Environmental Clearance shall be specific in regard to the remedial as well as precautionary measures that are required to be taken by the project proponent.

6. In the event the project proponent does not comply with the directions issued under the Environmental Clearance, the project work shall be liable to be stopped forthwith.

12. The application is disposed of with no orders as to costs.

**Swatanter Kumar**
**Chairperson**

**M.S. Nambiar**
**Judicial Member**

**R.S. Rathore**
**Judicial Member**

**A. R. Yousuf**
**Expert Member**

**Bikram Singh Sajwan**
**Expert Member**

New Delhi
31st May, 2016

**503004/2021/IA_III**

ÞITEM NO.22 + 36 COURT NO.1 SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A

RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 8762/2016

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR
CORPORATION OF INDIA LTD AND ANR. Appellant(s)

VERSUS

SOCIETY FOR PROTECTION OF ENVIRONMENT AND
BIODIVERSITY (SPENBIO) AND ORS. Respondent(s)

WITH

CIVIL APPEAL NO.9070 OF 2016

DELHI METRO RAIL CORPORATION Appellant(s)

VERSUS

VIKRANT TONGAD AND ORS. Respondent(s)

(With office report)

Date : 16/09/2016 These appeals were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE A.M. KHANWILKAR

For Appellant(s) Mr. Mukul Rohatgi,AG
(CA No.9070/2016) Mr. Annam D.N. Rao,Adv.
Mr. Sudipto Sircar,Adv.
Mr. Annam Venkatesh,Adv.
Mr. Rahul Mishra,Adv.
Mr. Abhinav Goyal,Adv.
(CA No.8762/2016) Mr. Maninder Singh,ASG
M r. Annam D. N. Rao,Adv.
Mr. Sudipto Sircar,Adv.
Mr. Annam Venkatesh,Adv.
Mr. Rahul Mishra,Adv.
Mr. Abhinav Goyal,Adv.
For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

Heard.

Issue notice.

Pending further orders from this Court, impugned orders passed by the National Green Tribunal, Principal Bench, shall remain stayed.

(MAHABIR SINGH) (VEENA KHERA)
COURT MASTER COURT MASTER